appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes for the readjustment of representation, and re-delimitation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such readjustment and re-delimitation are necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith up to the 29th August, 1969."

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह समय क्यों बढ़ाया जा रहा है। 29 अगस्त तक समय बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? इस कमेटी की रिपोर्ट जल्द आनी चाहिये।

श्री देवराव पाटिल: अध्यक्ष महोदय, इस सेशन में इस कमेटी का काम नहीं हो पायेगा, 1 जुलाई से उसकी मीटिंग होगी, जिसमें क्लाज़-बाइ-क्लाज़ कन्सीडेशन होगा। नेक्स्ट सेशन अगस्त में होगा, इसलिये अगस्त तक का टाइम लिया है, ताकि बार-बार न बढ़ाना पड़े।

श्री जार्ज फरनंन्डीज (दक्षिण-बम्बई): अध्यक्ष महोदय, एक साल से यह मामला ज्वाइन्ट कमेटी के पास है, आज फिर 6 माह का टाइम मांगा जा रहा है। इतना समय नहीं मांगा जाय, यह रिपोर्ट सदन के सामने जल्द आनी चाहिये, क्योंकि जिन मसलों को लेकर यह रिपोर्ट है, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस लिये इसमें समय निकालने की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री अ० सि० सहगल (विलासपुर): अध्यक्ष महोदय, हमें अपने एक्सचेकर को देखना चाहिये कि हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। आप इसके कर्ताधर्ता हैं, इस हाउस के मालिक हैं, अगर हम इस तरह से इन सब कमेटियों के टाइम लम्बे-लम्बे बढ़ाते जायेंगे तो इनके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। देश की हालत को देखते हुए, जितना ज्यादा काम हम कर सकते हैं हमें करना चाहिये। और ज्यादा समय नहीं लेना चाहिये।

MR. SPEAKER: They will try to finish it as quickly as possible. Now the question is:

"That this House do extend the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the readjustment of representation, and redelimitation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such readjustment and re-delimitation are necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith, upto the 29th August, 1969."

The motion was adopted.

12.29 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the Motion of Thanks on the President's Address. Out of the fifteen hours allotted by the Business Advisory Committee, six hours have already been taken. We will continue the discussion today and tomorrow. The Prime Minister will reply on Wednesday morning. Now Shri Yogendra Sharma will continue his speech.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, हम उस दिन निवेदन कर रहे थे कि हमारे देश में जो आर्थिक विषमता बढ़ रही है, साम्प्रदायिक विषमता बढ़ रही है, क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई विषमता की नींव पर हम राजनीतिक स्थिरता

और राष्ट्रीय एकता की इमारत नहीं बना सकते। यह विषमता क्यों बढ़ रही है, इस लिये बढ़ रही है कि हमारी सरकार ने ऐसी नीति अख्तियार कर ली है कि इन तमाम क्षेत्रों में सबल पक्ष को ये प्रोत्साहन देते हैं और जो दुर्बल पक्ष है, उस का दमन करते हैं। होना यह चाहिये था कि दुर्बल को प्रोत्साहित करते, उसकी रक्षा करते, उसको आगे बढ़ने का मौका देते और सबल पक्ष को नियन्त्रित करते, लेकिन इन्होंने उल्टी नीति अख्तियार की है। यही कारण है कि इस पूरे अभिभाषण में समाजवाद शब्द का उल्लेख तक गायब कर दिया गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो बहुत व्यापक मांग इस देश में उठी हुई है, उसका उल्लेख भी कहीं नहीं है, प्रीवी-पर्स को समाप्त करने की बात का भी कहीं उल्लेख नहीं है। यह वह नीति है जिसके ज़रिये से दुर्बल पक्ष कमजोर किया जा रहा है, नतीजा यह हो रहा है कि पिछले 2 सालों में 100 हरिजन कत्ल कर दिये गये और करीब इतने ही साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों का कत्ले-आम हो गया और इन तमाम कत्लेआमों की जिम्मेदारी हमारे गृह मंत्री पर है। हम स्वतन्त्र पार्टी के नेता आचार्य रंगा की इस बात से पूरे तौर पर सहमत हैं कि राजनीतिक नैतिकता का तकाज़ा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये।

अभी-अभी हमारे गृह मंत्री बिहार गये थे। गृह मंत्री जी जब आया राम गया राम की बात बोलते हैं, दलबदलूपन की बात बोलते हैं तो हमारे सामने उनकी जो प्रतिमा उभर कर आती है, वह है—"मुंह में राम, बगल में छुरी"—एक ऐसे ही आदमी को अपनी पार्टी का नेता और उसके माध्यम से बिहार का मुख्य मंत्री बनाने की साजिश करके आये हैं। हम कहते हैं कि वह साजिश करके आये हैं, क्योंकि अपने दल की मीटिंग के बाद ही उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने इस साजिश को रचा। ये दलबदलूपन की बात करते हैं लेकिन एक ऐसे आदमी को मुख्य मंत्री बनाने की साजिश कर रहे हैं जो पेशेवर दलबदलू है, आया राम-गया राम है, तीन-तीन बार दल बदल चुका है और हम समझते हैं कि ऐसे आया-राम-गया-राम की कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यही पुण्य शर्मा जी की पार्टी ने भी कमाया है, भोलाशास्त्री को नेता मान कर।

श्री योगेन्द्र शर्मा : तीन-तीन पार्टियां बदली हैं, आया राम-गया राम का काम किया है, ऐयर कमीशन के सामने यह चीज आ चुकी है कि ऐसे आया-राम-गया-राम की कीमत 2 हजार रुपये है। जिस व्यक्ति की कीमत दो हजार रुपये हो, उसको मुख्य मंत्री बना कर, उसके द्वारा बिहार में सरकार बनवाकर हम बिहार में क्या करने जा रहे हैं। ये राजनीतिक स्थिरता की बातें करते हैं, प्रजातन्त्र की बातें करते हैं—एक प्रकार से पाखण्ड की बातें करते हैं, ऐसे पाखण्डी गृह-मंत्री को तुरन्त निकालना चाहिये, वरना इस देश का राजनीतिक वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि आज जो हमारे देश में प्रजातन्त्र को खतरा है वह किस बात से है? बहुत से लोग जब खतरे की बात उठाते हैं तो शायद नक्सलबाड़ी की बात को लेकर बहुत हल्ला करने लगते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में हमारे देश में जो जन-धन और सम्पत्ति की बर्बादी हुई है वह किन शक्तियों के ज़रिये हुई है? यह बर्बादी हुई है साम्प्रदायिक शक्तियों के जरिये से, शिव सेना के ज़रिये से और आर० एस० एस० के जरिये से। आप इन फासिस्ट शक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध लगाने

के बजाये उनकी सरपरस्ती करते हैं। ऐसी फासिस्ट शक्तियों की सरपरस्ती करने वाले गृह मन्त्री का गृह मन्त्री रहना भारतीय प्रजातन्त्र के लिए खतरा है। यह बड़ी लज्जा की बात है। ऐसे गृह मन्त्री को जाना ही चाहिए।···(**व्यवधान**)···इस देश में पिछले दो सालों में जितनी खून खराबी, हत्यायें और लूट-पाट इन साम्प्रदायिक शक्तियों ने की हैं उसका सौवां हिस्सा भी नक्सलबाड़ियों ने नहीं किया है। ···(**व्यवधान**)···देशद्रोही वे हैं जिन्होंने बम्बई महानगरी को खून-खराबी और लूट-पाट की आग में झोंक दिया। सबसे बड़े देशद्रोही वही हैं। यदि ऐसे देश-द्रोहियों के प्रति आप सहानुभूति दिखलायेंगे तो यह देश रसातल में चला जायेगा। यदि बम्बई रसातल में गया तो वह नक्सलबाड़ियों की वजह से नहीं बल्कि शिव सेना की वजह से।···(**व्यवधान**)···

आखिरी बात वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में कह कर मैं समाप्त करूंगा। हम चाहते हैं कि विश्वशांति के हित में आपको वियटनाम से हमलावर अमरीकी फौजों की वापसी की मांग करनी चाहिए और जी. डी. आर. के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। इससे विश्व शांति की शक्ति बढ़ेगी। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि श्री बलराज मधोक ने जिस शक्ति सिद्धांत का सम्पादन किया है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह एक साम्राज्यवादी सिद्धांत है जोकि हमारे देश और राष्ट्र के लिये खतरा है और दुनियाँ के तमाम कमजोर देशों को खतरा है। हमारा देश कभी भी इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं कर सकता है।

SHRI A.K. GOPALAN (Kasergod): Mr. Speaker, Sir, the President in his Address has said that it was an appropriate occasion for the Government to present a realistic appraisal of the year under review. I am sorry to say that the appraisal was not realistic; it was only imagined. The Government is blind because it is not able to see what is happening around. It is also not able to understand what the people say. That is the reason why the President has drawn a picture which is a very bright picture and which has nothing to do with what is happening in the country today.

As far as the economic or political situation in the country for the last one year is concerned, it is one of unrest and turmoil. There was the student unrest. The studeut unrest was a part of the general unrest among the entire population. Dissatisfaction and a sense of frustration are pressing themselves into various forms and various sections of the people are coming out against the policies of Government.

I only want to point out certain things which the President has referred to in his Address. First is about agriculture. Referring to agricultural production, we are told that we have made a turning point in our agricultural production and that self-sufficiency in food is well within reach within the next two or three years. To prove their assessment, the Government cites foodgrains production in 1967-68 which is 6 million tonnes higher than the previous peak of 1964-65. To say the least, this is most misleading because as production increases the population also increases. So, to know the real trend in agricultural production we have to see what is the *per capita* production.

The real indicator is the *per capita* production. The *per capita* production, in 1968, is 2.7 per cent which is less than what was in the peak year of 1964. What is it in 1968-69 which is the year under review? In *Commerce*, an article of 15-2-69 states that the *per capita* agricultural production appears to have fallen slightly in 1968-69. From these figures, we see a consistent declining trend in the *per capita* agricultural production, particularly, in the food production. And we are asked to believe that self-sufficiency is round the corner. If the Government believes that, they are deceiving themselves and also others.

Even the declining trend in *per captia* production has to be supported hereafter

by steeply increasing outlays in agriculture. In the First Five Year Plan, to achieve a 22 per cent increase in agricultural production, we had to spend Rs. 218 crores. In the Second Plan, for a lesser rise of 20 per cent, we had to increase the outlay to Rs. 549 crores. In the Third Plan, for a much reduced rise, that is, a mere 11 per cent, we had to increase the outlay to Rs.660 crores. In the Fourth Plan period, it will be more and this will lead to more reliance on P. L. 480.

They say that there is a bumper crop and there is an increase in production. That is what we are told. But as far as the *per capita* consumption is concerned, we know that there is only 3 ounces ration in some States, 4 ounces ration and 6 ounces ration in some States. As far as the people are concerned, whether there is a bumper crop or increase in production, what they get is far less. It is just like saying, water, water everywhere but not a drop to drink.

The President has also said, in his Address, about the agricultural production and the enthusiasm of the farmers supported by fertiliser and other things. It is true that there is a little more production of fertilisers. But what about money for persons to buy fertiliser ? So, the purchasing power of the farmers is very important. In the last 20 years, our experience is that we have not been able to have more food production because there is a basic reason why we are not able to do so. We can increase food production only if 30 to 40 per cent of the population who live on land, specially, the agricultural labourers, are given money, are given land, and are given all help. In many States in India, even where there is land reforms legislation, where there is ceiling fixed, that is not implemented and, in other places, as far as the present availability of figures about cultivable waste land and fallow land is concerned, 4.35 crores of acres of cultivable and fallow land are available in India. Why does the Government even today allow the cultivable waste land and fallow land under their control and under the control of private individuals. Why have they left it uncultivated ? Why don't they issue an Ordinance and give land, a little money and irrigation facilities to agricultural labourers and see that the production increases. Only yesterday, we read in papers the Minister of Irrigation saying that the money for irrigation is less. Even if there is fertiliser, unless there are more and more irrigation facilities, it cannot be increased.

Now, coming to the question of industrial production, we are told that the process of recovery has bugun. What is the recovery ? We are told that there is likely to be an increase of 5 to 6 per cent during the year. Even suppossing that anticipation is true, it falls short of the annual average rate of increase from 1954 to 67 which was 6.5 per cent. The increase in industrial production in real terms for a year during the Third Plan period stood at 7.6 per cent whereas for the first three years of the Fourth Plan period, the figures stood at only 6.1 per cent. This means that, even if the rate of increase for all the three years of the Fourth Plan period is put together, it falls short of one year's average of the Third Plan period.

It is said that we are on the path of recovery. Take the index of fresh capital raised. This is also an indicator of recovery or otherwise in the industry. If you take the base year 1960 as 100, the index rose to 113.9 in 1965, but dropped to 80.7 in 1966 and again dropped further to 76.9 in 1968. In fact, the index which was 90.7 in 1967 dropped to 76.9 in 1968. You see from the figures that there is a continued declining trend in the index of fresh capital raised. How can we say, when the fresh capital raised is lesser every year and the percentage is lesser that the process of recovery has begun ?

Take also the machine-tool industry. As far as machine tool industry is concerned, if the orders received by the machine tool industry are more and more, then that is an indication of the recovery. Any process of recovery in industry will be clearly reflected in greater activity in the machine tool industry. In 1967-68, the H. M. T. secured orders for 2,276 machines whereas in 1968-69 the orders secured dropped to 1,217 machines, i. e.,

[Shri A.K. Gopalan]

almost to half. Yet, the Government is saying that the process of recovery has begun.

Then, the closure of textile mills is another factor. The closure of textile mills remains a continuing phenomenon in the country. I have got the figures of only one State. The number of textile mills closed in Tamil Nadu, which was six in the beginning of 1967, rose to 21 in 1968 and further rose to 29 at the beginning of 1969. Continuously, every year, more mills are being closed down.

This is the fate of handlooms also. I have no figures, but I can say that it is a fact and a reality that in many States in India, handlooms are closed and that also, for want of foreign market and other things. So, handlooms are also being closed. Yet, we say that the process of recovery has begun ! I am quoting this from '*Commerce*' dated the 15th February, 1969 :-

> "Reflecting partly the lustreless demand conditions and partly the slackened tempo of expansion of the industries, the industrial output may not show vigorous expansion in the immediate months ahead, and what is worse, it may relapse in stagnation".

As far as small industries are concerned, I can say that in Kerala the position in regard to cashew industry, the coir industry and the beedi industry is very bad. The beedi industry is completely closed. In cashew, thousands of persons are unemployed; many small factories are closed. In coir also, the fate is the same. As far as small industries are concerned, insted of developing, most of the factories are going out of function. Therefore, there is no meaning in saying that we are on the path of recovery. I can only say that the story of the process of recovery is either a figment of imagination or a wishful thinking. If for Government 'recovery' means the recovery from the shock that they had during the mid-term elections, then I have no objection to that. But there is no question of recovery as far as industrial production is concerned.

The next point that has been referred to is about prices. Regarding prices we are told that there is improvement in industrial production.

It has also been stated that there has been price stability. But I have shown that there is no improvement at all. When a number of commodities like tobacco, fibre, minerals. textiles, jute, metal products, chemicals etc. continued to maintain the same increasing trend of prices during 1968, I do not know how Government could say that the prices had been stabilised.

The real consumer index for the working class for the 12 months in 1967 which stood at 209 rose to 215 during the twelve months of 1968. With the rising trend persisting, Government are telling us that there has been improvement and they are trying to deceive themselves by trotting out the false story of stabilisation of prices.

When Government say that the growth in agriculture and industry is having a salutary effect on the unemployment problem, I would submit that that is also not correct and not real, I feel that Government are minimising the seriousness of the problem of unemployment. Take for instance educated unemployment. Engineers, doctors, technicians, ITI trainces and polytechnic people are unemployed in thousands. In Kerala alone, according to the figures of last year, the ITI boys who had been trained numbered about 17,000. As far as the engineers are concerned, we know that a year ago, some engineers came and offered satyagraha before Parliament. As far as doctors are concerned, there are thousands of doctors who are unemployed. The doctors are walking on the streets to see the patients, while the patients are walking along the road to see the doctors; the one dies because of not getting treatment while the other dies because of not having patients to treat.

So, the question of unemployment is a very serious question. That is the reason why amongst the students today everywhere in the country there is so much of

unrest and dissatisfaction and this dissatisfaction and unrest has moved them towards certain paths which we may not like.

The backlog of unemployment at the end of the Third Plan was 10 million. The tempo of economic development was less and under the recession of the subsequent three years, when the same trend is taken into account, we find that the backlog of unemployment on the eve of the budget works out to be 12 million. During the last nine months there were more closures and retrenchment which have also thrown out of employment many thousands of workers. In Bengal about 6000 jute workers have been thrown out. So, it is a very pathetic situation. I am sorry to say that in the Address, the seriousness of educated as well as uneducated unemployment has not been brought out.

Another question that has been referred to in the Address is about the Central Government employees.

The President has said that Government are going to set up a kind of machinery to promote harmonious relations between the Government and their employees and for redressal of the employees' grievances by having joint consultation and compulsory arbitration.

The agitation of the Central Government employees was an expression of the discontentment felt by the mojority of the people, discontentment arising out of the increasing difficulties, the difficulties of the day-to-day life and the burdens of life. This was the reason which prompted the Central Government employees to go on strike. But there was ruthless repression, and all norms and procedures of the Central Civil Services Disciplinary Rules were thrown to the winds, and there was victimisation. That was the keynote of the whole thing. I do not want to go into the question of what happened after the strike. Discretion was vested with the officers that those who were innocent could be taken back. The press note dated the 7th January, 1969 was to the effect that if any Government servant was under suspension on the ground only of his arrest or prosecution in connection with the offences relating to the strike and he had been acquitted by the court, he would be permitted to rejoin duty. Departments had been advised that representations regarding injustice to innocent persons may be examined on merits. But these things have not been done and I could point out cases where the instructions contained in the press note had been violated.

There are several cases where some of the Central Government employees had only absented themselves on that day; but they have also not been taken back and the pressnote of Government has been disregarded. They were not in the list of strikers, but they were unable to be present on 19th September. They were not prosecuted, nor were they involved in any active role in the strike. In the railway branch office at Olavakot, there were several such cases like this. There are many others in other places also.

Then there are cases where the State Government of Kerala withdrew the cases. Unfortunately, there have developed some differences of opinion between the Central Government and the State Government on this point. The Kerala Government withdrew the cases, but secret instructions were sent from here to the heads of the departments to oppose the withdrawal Hence the cases are continuing. The State Government is primarily responsible for law and order, but heads of departments have been instructed to act contrary to the decision of the State Government in this matter.

I read in the papers that in Punjab also, the State Government has ordered the withdrawal of the cases and released them. I do not know whether the same position will obtain there in regard to the Central Government's attitude.

Out of 10,000 Central Government employees in Kerala, 888 have either been dismissed or discharged. If the Central Government here do not like the State Government of Kerala, is it right to visit the former's vindictiveness on the Central Government employees also ? Yet that was what was done in Kerala.

[Shri A. K. Gopaln]

Close on the hostile attitude of Government and vindictiveness towards the employees, is the proposal to bring forward a Bill in this session banning strikes. I want to ask whether banning the right to strike and keeping 8,000 employees out, either suspended or out of service, putting them and their families to great suffering and hardship and also punishing half their number—will create the right atmosphere for the re-establishment of good relations between Government and the employees. If the President wants that there must be these good relations, as he says, it is necessary that all of them must be taken back. This is the first step required towards that end.

Then reference has been made to the joint consultative machinery. This question arises only when the recognition of the unions remains. But we find that most of the unions have been de-recognised. That being so, I do not see how it is possible to create good relations between Government and their employees.

The next important aspect which has not received attention is Centre-State relations. When there were only Congress Governments in power in the Centre and in the States, there was no question of any friction or difference. But now the position is different. Today, there are differences even between the Centre and the Congress-governed States. Shri Brahmananda Reddy has given expression to that. There is also the case of Maharashtra. It is a fact today that there are differences between the Central Government and the State Governments at the policy level. That being so, these must be discussed and thrashed out in order to iron them out. We should see what changes are called for to ensure good relations. When there are non-Congress Governments, not one or two, but many, this is all the more necessary in the interest of harmonious Centre-State relations. But this has not been done. After meeting the Prime Minister, the Chief Minister of Kerala said even yesterday that these differences will only stiffen if adequate steps are not taken in time. The Prime Minister speaking in this House said the other day:

> "I have said this on various occasions, and I would repeat here, that we offer full co-operation to all those who have been elected and all the governments which have come or will come into being, and the Government of India will deal fairly with those States."

I am very glad about the sentiment but let us examine whether the Government of India dealt fairly with all the States, especially the States ruled by the Non Congress Governments. The Prime Minister says "we"; I do not know whether it means all the Ministers in the Government or only some, because I can point out to the utterances and deeds of some of the Ministers and other highest leaders of the Congress which show that they do not want co-operation; they want to topple these Governments. The Congress President Mr. Nijalingappa says on January 5 that if the reports received by him about lawlessness in Kerala were correct, the time had come for the Centre to take over the Government of the State. If the time has come, as President of the Congress it is his duty to tell the Central Government. Why should he say this while addressing a public meeting ? They want to demoralise the officers, especially the All India Services: Be careful; this Government will be toppled and they will go away; so, do not do as they say.

I can at least understand other common people saying things. On 21 October, Mr. Desai, the Deputy Prime Minister speaking to CRP Jawans and officers on the 20th anniversary celebrations of the CRP told the audience that.

> "If Namboodiripad Government persisted in its anti-constitutional activities and rendered the constitutional functioning of the administration impossible, the Centre would not hesitate to intervene and impose President's rule".

What has this to do with the CRP celebrations ? If you say so in some public meeting, it has some sense. They say so to demoralise the officers. I do not want to take objection to speeches. But where do they say these things ?

But what Mr. Panampilli Govinda Menon, the Minister in charge of 'lawlessness' in Kerala says is very interesting. It is not one speech; I have a series of speeches with me but I have no time to quote them all; I shall refer to a few specimens. In Trichur last October he said :

> "The Centre is strong enough and fully capable of dealing with any constitutional problem that it may be faced with and if found necessary, the Kerala Government can be dismissed under article 365 of the Constitution and the Central directive enforced."

He then says something more interesting :

> "When the ruling parties have unleashed such violence under the protection of the State Government the Congress men must firmly resist and beat them back even if, in so doing, they have to take the law into their hands."

He then declared :

> "The sort of administration now running the State is something that no self respecting person can possibly tolerate."

He further says that in this situation he would without fear exhort people to strongly resist that Government with suitable means, even if in the process he lost his ministership or was arrested. He says that the law must be taken into the hands by the members of his party. Resist them and beat them back—that is what he says.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : He must be arrested under the Goondas Act.

13 Hours

SHRI A. K. GOPALAN : He went on to say :

> "There may be persons who will ask whether such resistance would not invite clashes and violence."

Shri Menon himself answered it : "That is something which is inevitable". I would be glad if the policy of the Congress is that violence and clashes are inevitable. If that is so, let us prepare ourselves for that. Then, Mr. Menon said:

> "It is likely that some may fall wounded in the battle. Some may even die. But no one has been born yet who has been secured against death."

Can a Central Minister, especially not one in charge of Fisheries, but in charge of law, say these things ? I wrote to the Prime Minister about these things. But he denied it after sometime. Only a shameless coward will deny what he has said. When these things come in the *Kerala Kaumudi* with a circulation of more than a lakh, which is an anti-communist paper, surely after one month he would have denied it through the paper itself. He did not do it.

Addressing the meeting of the District Congress workers, Mr. Menon exhorted Congress workers to rise like lions and fight back bravely the violence unleashed by the masses. Sir, if this kind of speeches are made, how can anybody expect the Centre-State relations to be cordial ? It is not a question of one or two speeches. Whenever Parliament is in recess, he goes to Kerala, he makes these speeches which are published in the papers and he never denies them in the paper. I am sorry that while on the one hand the Prime Minister wants that Centre-State relations should improve, on the other Central Ministers are making this kind of speeches.

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade) : There is nobody on the Treasury Benches to take note of the points in the speech.

MR. SPEAKER : There are two Cabinet ministers present.

SHRI A. K. GOPALAN : The president refers to certain disturbing trends in our national affairs—parochial, regional, caste and communal trends. But who is responsible for it ? Is it not the Congress

[Shri A. K. Gopalan]

Government which is responsible ? As far as Shiv Sena is concerned, when the first meeting was organised, Mr. Chavan presided over it and the slogan was "idly, sambar go back" and four Udipi shop-keepers were beaten. After the meeting, lakhs of people marched shouting "idly, sambar—go back." It means that South Indians must go back. The State Government as well as the Central Government should have taken this seriously. It is not a political movement, but a movement where you divide State and State. There were so many instances. I had written to the Chief Minister and also the Prime Minister. The first victims were South Indians. When I went to Bombay they used to give me petitions. Many huts were burnt and many people were beaten. Every time there is a meeting of Shiv Sena we have seen that all the hawkers, who do business to earn their livelihood, just run away. If any hawker is there he will be beaten. This fact had been brought to the notice of Government.

There is no question of any unity. What is the effect of it, what is the effect of the last attack ? *Kerala Kaumudi*, the same paper, has come out with an editorial saying that if our people are sent back they become unemployed. There is very great unemployment in Kerala and therefore people go out in search of jobs. If they are turned out from those places—I do not subscribe to what the paper has said—then do not say, the paper adds : "We are part of India". People are not able to get jobs in Kerala and they cannot go outside also. What does it come to ? The first attack was on South Indians. Then they attacked the Communist Party and the Government thought it to be good because the Communist Party would be eliminated. Then they attacked Shri Chavan himself.

There is the Telengana issue. I was one of those who said that there must be a Vishal Andhra. When we fought for Vishal Andhra, if a man from Andhra feels that a man from outside has no place there it cannot be tolerated.

As far as casteism is concerned what is the policy of Government? I can understand the policy of Jan Sangh. The Jan Sangh is having a programme there against what is called Moppilastan. What is this Moppilastan ? Nobody here will know what is Moppilastan in Kerala. Malabar was one district. After the formation of the State it was divided into three districts. Now the Government says, because there are some pockets in some four districts two of them could be made into one and have another Malapuram where the Muslims are in a majority. As far as outside areas are concerned they are not in a majority. They are pockets of Hindus and Muslims. If one or two more districts in Kerala are formed it does not go against the security of the State. It has also got nothing to do with the defence or foreign policy of the country. How can you then say, it is formation of Moppilastan ? In that way, if you call a district Moppilastan because there are one or two more Muslims, then every district in Kerala is a Hindustan or a Christianistan because every district in Kerala has a Hindu majority or a Christian majority.

What are the villages that are to be added to the new distriet has not yet been decided. Even before that has come the slogan of Moppilastan. The Congress is not openly doing it but the Congress is openly supporting it. What will be the result of that ? I want to ask this question to the Congress leaders. I warn them to be very careful. Once you raise the communal passion, you must remember how difficult it was in 1921 for the British Government with all its army to control it.

I went to Bengal during the elections. The Congress leaders had been doing propaganda asking people not to vote for the UF Government, not to vote for Biharis. They were saying that the UF Government will be driven away. Why make Bengal and Bihar fight each other ? Why do you rouse the feelings of the people of Bihar and others in order to see that the Congress Government remains in power ? If you use casteism and communalism towards this end it will be roused in such a way that no military or any other power will be able to control

the situation. Communal parochialism has developed in such a way that unless the Congress takes the lead now, whether the Congress comes to power or not, a stage will come when it will be out of control. If this is roused for some purpose at the present time, there is no doubt about that will mean not only the ruin of the Congress Party but also the ruin of the country.

MR. SPEAKER : On the first day a large number of Congressmen took part in the discussion on the President's Address, about 12 out of 17. While 12 members have spoken from the Congress, only 5 have spoken from the opposition. Of course, it is not the number but the time taken by each party that counts. I have to give opportunity to two or three independents also, like Shri Mandal, Shri Kripalani and others, who have given their names. This discussion will continue the whole of today and tomorrow. On Wednesday morning the prime Minister will reply. We will now adjourn for lunch till 2.10 p. m.

The Lok Sabha adjourned for lunch till ten minutes past fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Ten minutes past Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री शिवनारायण (वस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों के सामने जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए प्रस्तुत किये गये धन्यवाद-प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं इस सरकार का ध्यान पटेल कमीशन की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। हमारे एक्स-फ़ाइनेन्स मिनिस्टर, श्री टी०टी० कृष्णमाचारी ने मुझे यह आश्वासन दिया था—श्री भगत इसके साक्षी हैं—कि बलिया और बस्ती को भी पटेल कमीशन के अन्तर्गत लाया जायेगा। उस ज़माने में श्री के० डी० मालवीय भी हमारे मिनिस्टर थे। इसके बावजूद आज तक हम लोग नेग्लेक्टिड हैं। प्रैज़िडेंट्स एड्रेस में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। बस्ती, बलिया और गोरखपुर वह क्षेत्र है, जो कि हिन्दुस्तान की ग़रीबी का जिन्दा चित्र है। गवर्नमेंट की मशीनरी के द्वारा उस इलाके की ग़रीबी और पिछड़ेपन के बारे में जांच की गई है और रिपोर्ट दी गई है। हम भी आये दिन उसके बारे में आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन आज तक सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी है। वहां की जनता में बहुत असंतोष है। **क्रमिंग ईवेन्ट्स कास्ट देयर शैडो बिफ़ोर।** यह खतरे की घंटी है। इसलिए सरकार को इस बारे में सावधान रहना चाहिए।

मैं भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, डा० त्रिगुण सेन और श्री भागवत झा आज़ाद, को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे अध्यापकों के लिए तीन करोड़ रुपये दिये। लेकिन आज भी डिग्री कालेजिज़ के हमारे अध्यापक अनशन कर रहे हैं। उनकी मांगें उचित हैं। मैंने इलेक्शन के समय उन्हें यह एशोरेंस दिया था कि मैं पार्लियामेंट में उनकी वकालत करूंगा। मैं प्राइमरी टीचर्ज से लेकर यूनिवर्सिटी के टीचर्ज तक को कहना चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट में मैं अपने आपको उनका रिप्रेजेन्टेटिव समझता हूं। "गुरु से कपट, साहु से चोरी, की होयें निर्धन, की होयें कोढ़ी।" सरकार से मेरी अपील है कि वह इन गुरुजनों की सही मांगों को पूरा करे।

किसी भी मुल्क की प्रगति और विकास के लिए मीन्ज़ आफ़ काम्यूनिकेशन्ज़ बहुत जरूरी हैं। हमारे गांवों के डेवेलपमेंट के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सड़कों के जरिये एक दूसरे के साथ मिला दिया जाये। हमने मांग की है कि हमारे यहां सड़कें बनाई जायें और उन्हें पक्का किया जाये। बस्ती

[श्री शिव नारायण]

ज़िले में राम-जानकी रोड एक हिस्टारिकल रोड है, जिससे सारा हिन्दुस्तान परिचित है। हमारे स्पीकर साहब जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो वह और प्राइम मिनिस्टर अयोध्या गये थे। उस अवसर पर मैंने उन्हें अपनी कांस्टीट्युएन्सी दिखाई थी। मेरी मांग है कि राम-जानकी रोड जो बन रही है, उसको पूरा किया जाये। बस्ती जिले से यह एक बड़ी डिमांड है। डुमरियागंज से हमारे एक्स-मिनिस्टर चुनाव लड़े थे, लेकिन वह कांस्टीट्युएन्सी हमारे हाथ से निकल गई। अब जनसंघ उसको रिप्रेजेन्ट करता है। लेकिन इस बारे में जनसंघ वालों के मुंह पर भी ताला पड़ा हुआ है। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूँ कि वह यू० पी० गवर्नमेंट को हिदायत दें कि वह शाहपुर से गोंडा तक की सड़क और उस क्षेत्र की अन्य सड़कों को जल्दी बनवाने की व्यवस्था करे। मैं नेपाल बार्डर पर रहता हूँ। डिफेंस के पायंट आफ़ व्यू से भी वे सड़कें बननी चाहिए।

मेरी कांस्टीट्युएन्सी में गणेशपुर के पुल को भी बनवा दिया जाये, ताकि हमारे यहां के किसान यह अनुभव कर सकें कि यह सरकार गांधीजी के राम-राज्य के आदर्श पर चल रही है और बस्ती शहर मिल जाये।

ईस्टर्न यू० पी० के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर जूट या सीमेंट फैक्टरी लगाई जाये और इसके साथ ही कुछ स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज भी वहां पर स्थापित की जायें।

मेरे इनविटेशन पर प्राइम मिनिस्टर मेरी कांस्टीट्युएन्सी को देखकर आई हैं। मेरे जिले में उनकी नौ मीटिंग्ज हुई। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी जांफ़िशानी, मेहनत और ईमानदारी के साथ हमारी तरफ़ से प्रचार किया। जनसंघ ने यह चार्ज लगाया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जनसंघ वालों को गालियां दीं। लेकिन वह ग़लत बात है। जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, उसी तरह, संतुलित और उचित भाषा में वह बोलीं। उन्होंने एक, डेढ़ लाख लोगों की मीटिंग्ज़ को एड्रेस किया और वह बड़ी संजीदगी के साथ बोलीं। उन्होंने बड़े बाप की बड़ी बेटी की तरह बात की। उन्होंने कोई छोटी बात नहीं कही।

माननीय सदस्य, श्री अटलबिहारी वाजपेयी, ने यहां पर भाषण देते हुए कहा कि ग़लत औरत ग़लत जगह गई है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि "मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः पश्यति सः पंडितः", अर्थात् जो पराई बहू-बेटी को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले की तरह और सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वही पंडित है। यह पंडित की परिभाषा है, लेकिन श्री वाजपेयी की पंडिताई उस दिन फेल हो गई। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हमने सदा अपनी मां-बहनों की पूजा की है। उन्होंने जो कुछ कहा, वह भारतीय संस्कृति नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों को गली-गली में बड़ी-बड़ी गन्दी बातें कही गई, लेकिन हमने उनको चुनाव में मात दी।

बंगाल, उड़ीसा और बिहार आदि में जो भी गवर्नमेंटें बनें, मैं उनको वेलकम करता हूं, लेकिन वे स्टेबल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। मैं ख़ास तौर पर बंगाल से कहना चाहता हूं कि वह आजादी की लड़ाई में हमारा अग्रदूत रहा है। वह रेवोल्यूशन का सिम्बल रहा है। बंगाल के लोगों ने अंग्रेज पर बम और गोलियां चलाई और स्वराज्य लिया। वह सुभाष और रासबिहारी की जन्मभूमि है। वहां चाहे कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट बने और चाहे किसी अन्य दल की, लेकिन वह एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए और पांच साल

तक चलनी चाहिए । हम उसके साथ को-आपरेट करेंगे । मैं सैंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि वह भी उसके साथ को-आपरेट करे । जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर मैं बंगाल का गवर्नर होता, तो

I would have given a long rope to Mr. Ajoy Mukerjee to hang himself with it.

केन्द्रीय सरकार को इस बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी । राजनीति में बड़ी स्थिरता से कछुए की चाल सरकार को चलनी चाहिए, खरगोश की चाल नहीं चलनी चाहिए । मैं इस गवर्नमेंट को हिदायत कर रहा हूं । स्टेबल गवर्नमेंट के पक्ष में मैं भी हूं ।

पाकिस्तान और चाइना दो दुश्मन हमारे सिवान पर खड़े हैं । मैं आज मुल्क से अपील करता हूं और आल अपोजीशन पार्टीज़ से अपील करता हूं कि जो हमारे नौजवान 20 वर्षों के हैं उन्हें बन्दूकें अपने कन्धों पर रख कर देश की रखवाली करनी होगी । मैंने अपने एलेक्शन कैम्पेन में अपील की और आज फिर अपील करना चाहता हूं कि आपस में हम चाहे भले ही 100 और 5 रहें लेकिन दूसरों के मुकाबिले में हम और आप मिलकर 105 रहें, यह हमारी नीति रही है । मैंने पब्लिक में कहा और आज यहां कहना चाहता हूं कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, इससे बड़ी बेईमानी राजनीति में कोई कर नहीं सकता । गुरु को मरवा दिया कृष्ण ने । लेकिन हम और आप में से दो बोरा नमक किसी ने चुराया या दो बोरा चीनी किसी ने चुराई तो उसको बहुत गालियां दीं, मगर पब्लिक ने कहा इनके लिए दे आर वर्स दैन अस । और इसका रिजल्ट लोगों के सामने है । मैं चाहता हूं कि मुल्क में स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए ।

ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में प्रेसीडेंट ने कहा कि बड़ा संतोष है, छः मिलियन टन के करीब मुनाफा हुआ । मैं कहना चाहता हूं 6 मिलियन टन कम है । मैं किसान का बेटा हूं । सरकार की जो नीति है, सरकार की नीति दुरुस्त है लेकिन जो मशीनरी नीचे है वह दुरुस्त नहीं है । उसकी नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं होता । किसान को ठीक समय पर पैसा नहीं मिलता । आई वांट क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन वरना कल्याण होने वाला नहीं है । जितने सरकारी नौकर हैं इन्होंने स्ट्राइक किया । यह हमसे तनख्वाह मांग सकते हैं, डीअरनेस मांग सकते हैं लेकिन स्ट्राइक पर नहीं जा सकते । दे कैन नाट गो आन स्ट्राइक···(**व्यवधान**)···अध्यक्ष महोदय, वकालत इन्हीं की कर रहा हूं लेकिन दिमाग में, भेजे में मिट्टी भरी हुई है ।

मैं यह कह रहा था, ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए हमको पानी दे दो ।

पानी राखो पात्र में बिन पानी सब सून ।
पानी गए न ऊबरें मोती मानुष चून ।।
इस पर अमल करे हमारी सरकार ।
हम को पानी दे वक्त पर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्राइम मिनिस्टर से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं । यह फोटो छपी है प्राइम मिनिस्टर की इस इंग्लिश बुलेटिन में । मैं अंग्रेजों को लानत भेजता हूं, उस विल्सन को, उनके एटीकेट में दिया हुआ है-- लेडीज फर्स्ट । लेकिन यह इनका चित्र देख लीजिए । उलटा कर दिया । सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट की प्राइम मिनिस्टर और वह लेडी प्राइम मिनिस्टर, शी इज सिटिंग इन दि सेकेंड रो । बिलकुल मैं नाथ पै के साथ इस में सहमत हूं । यह हिन्दुस्तान के सम्मान की बात है । मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं और प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आइन्दा इस कामनवेल्थ में आप भी अपने किसी सेकेंड रेट मिनिस्टर को भेज दीजिए । Let her send one of her State

[श्री शिव नारायण]

Ministers. Let Mr. Wilson know what we Indians are. Send one of your second-rate Ministers.

आज भी हमको दासानुदास समझते हैं विलसन व विल्सन के दिमाग ठीक कर दीजिए। सूबा उत्तर प्रदेश के बराबर विल्सन का मुल्क है, मैं हिन्दुस्तानियों से कहना चाहता हूं कि हम और आप इस मुल्क के ...(**व्यवधान**)... व्हाट नानसेंस इज दिस ...(**व्यवधान**)..मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि आइन्दा आप जब कामनवेल्थ में जायं तो सेकेंड रो में आपका स्थान नहीं होना चाहिए। यह चित्र देखकर हमें बड़ा पेन हुआ जब हमने इस पैम्फलेट को पढ़ा। इंग्लिश एटीकेट में लेडीज फर्स्ट कहा है, इट इज देयर कल्चर, नाट अवर कल्चर और सेकेंड लाइन में खड़ा कर दिया। यह हिन्दुस्तान की आबरू का सवाल है। मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूँगा कि आइन्दा कामनवेल्थ हो तो किसी स्टेट मिनिस्टर को भेज दें तब विल्सन को पता हो और वाशिंगटन को पता हो। जिस शान से आप यू० एन० ओ० में बोली थीं, उसी शान को निबाहिए। प्राइम मिनिस्टर आ गई हैं, मैं उनसे फिर इस बात को कहना चाहता हूँ और जो आप ने हमारे यहां एलेक्शन में मेहनत की उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूँ। जनसंघ को मैंने जवाब दे दिया।

19 सितम्बर के बारे में मैं गवर्नमेंट से निहायत अदब से अपील करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने गलती की, आपने बहुतों को माफ कर दिया, बहुतों पर अभी मुकदमे चल रहे हैं। कहा है

क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात।

उनको माफ़ कर दीजिए और उनकी जगहों को वापस कर दीजिए। अगर वह अक्लमंद होंगे तो आइन्दा ऐसी गलती नहीं करेंगे। टीचरों का जो मामला है सरकार उसको इग्नोर न करे। मैं प्रेसीडेंट के ऐड्रेस का समर्थन करता हूँ। एक छोटी सी बात और बाकी है, वह मैं पढ़े देता हूं :

Andhra Pradesh was born on 11th November, 1956 by the integration of Telengana in Andhra, the Andhra region comprising of 11 districts and the Telengana region comprising of 9 districts. The basis of the integration was a gentlemen's agreement. Under this agreement, several safeguards in regard to employment and economic development were given to the Telengana people but they were not implemeted. According to the agreement, the Telengana revenue surplus was to be spent on Telengana development but this was not done, now, I come to the Harijan population in Andhra Pradesh. There are 49 lakhs Scheduled Castes in Andhra Pradesh; the distribution of Harijans is 28 lakhs in Andhra region and 21 lakhs in the Telengana region, which comes to a proportion of 4 : 3. But the allocation on Harijan welfare made by the State Government was only in the ratio of 3 : 1 in terms of money, that is, three parts to Andhra region and one part to the Telengana region. Thus the Harijans in Telengana have suffered during the last twelve years. The Andhra Pradesh Government have clearly admitted on the 19th January, 1969 in an all-party accord that lapses had occurred in the implementation of safeguards given to the Telengana people. The Central Government should undertake the responsibility of implementation with a view to restoring confidence in the people as suggested in the SRC report.

मैं हरिजनों के बारे में प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, मैं विदेश में था, सन् 21 के बाद हम लोग इस देश में आए, लेकिन यहां पर हमारी जिम्मेदारी नेहरू और गांधी ने ले रखी थी, हरिजनोत्थान की जिम्मेदारी ऋषि दयानन्द ने ले रखी थी। आज भी यह शिवनारायण के कन्धों पर नहीं है, प्रधानमंत्री जी के कन्धों पर है। मैं कहना चाहता हूँ, हरिजनों के साथ बड़ा जुल्मो-सितम हो रहा है। अन्त में मैं केवल दो लाइन कह कर खत्म करता हूँ।

न पैमां शिकन हैं न गद्दार हैं हम,
वतन परवरी के खतावार हैं हम ॥

इन चन्द शब्दों के साथ मैं प्रेसीडेंट साहब के ऐड्रस का समर्थन करता हूँ।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि ऐसे मौके पर सरकार के लिए यह उचित है कि वह इस वर्ष की वास्तविक स्थिति को सामने रखे और अगले वर्ष में अपनी नीतियों और उद्देश्यों की मोटी रूपरेखा बताए। यह राष्ट्रपति ने अपने भाषण में प्रारम्भ में कहा है। इसकी रोशनी में जब मैं वह भाषण सुनता गया और उसके बाद जब उसको ग़ौर से पढ़ा तो काफी निराशा हुई। वास्तविकता की दृष्टि से तो भाषण खोखला मालूम होता है और अपनी नीतियों के बारे में, यानी आज जो परिस्थिति है उसको सुधारने के लिए जो नीतियां अख्त्यार करनी चाहिएं उसकी दृष्टि से जब मैं देखता हूँ तो यह भाषण बिल्कुल बेजान सा मालूम होता है। हमारे इस देश में आज स्थिति क्या है ? वास्तविक रूप में देश में आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से परिस्थिति अच्छी नहीं है। उसके बारे में सबूत रोजाना हम लोगों को दिखाई देते हैं। उसके निशान हैं मजदूरों की हड़तालें और सरमायेदारों की तरफ से तालाबन्दी, मिलों का बन्द हो जाना, बेरोजगारी का बढ़ना, हमारे विद्यार्थियों में असंतोष, भाषा और प्रान्त को लेकर खूंरेजी और झगड़े। उससे यह पता चलता है कि देश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हम लोगों को इसका कोई इलाज जरूर करना चाहिए। इस अभिभाषण में हमें उसका कोई इलाज दिखाई नहीं देता। पहले तो निदान ही ठीक नहीं है, जब निदान ही ठीक न हो तो हकीम नुस्खा क्या लिखेगा। पिछले साल, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की गोलियों से जितने आदमी मारे गये, उतने शायद ही कुल मिलाकर पिछले 20 सालों में मारे गये होंगे।···

एक माननीय सदस्य : आंकड़े बतलाइये।

श्री एस० एम० जोशी : 100 से ऊपर हैं, किसी भी साल के आंकड़े से मिला लीजिये। बम्बई में 58 आदमी मारे गये। मैंने एक प्रश्न पूछा है, उसका पूरा उत्तर अभी नहीं आया है, लेकिन···

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतूल) : 20 साल में तो बहुत मारे गये होंगे, एक साल में उतने नहीं मारे गये होंगे ?

श्री एस.एम. जोशी : 150 आदमी किस साल में मारे गये ?

श्री मु० आ० खाँ (कासगंज) : कम्यूनल राइट्स में कितने मारे गये ?

श्री एस० एम० जोशी : ठीक है, इस बात को छोड़ दीजिये, लेकिन यह तो सही है न कि इस साल सबसे ज्यादा मारे गये—आप इतना ही मान लीजिये कि इस साल में ज्यादा से ज्यादा आदमी मारे गये। यहां संविद की सरकार या कांग्रेसी सरकारों का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है। हम लोगों को यहां बैठ कर देश के लिये सोचना चाहिये।

मैं तो यह समझता हूँ कि पहले इसका सही निदान होना चाहिये। निदान सही करके अगर हम उसका उपाय सोचते तो शायद रास्ता नजर आ जाता, मगर यहां तो निदान ही अच्छा नहीं हुआ। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में एक बात और कही है---जिसे वह 20वें परिच्छेद में कहते हैं—

"सरकार को मालूम है कि देश में पूरे तौर से आर्थिक विकास की समस्याओं के हल के लिए राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है।" यह तो प्राथमिक चीज है। लेकिन जहां तक स्थिरता की आवश्यकता का प्रश्न है, पूरे तौर से क्या, अधूरे तौर से भी नहीं है। राजनीतिक स्थिरता को हम

[श्री एस० एम० जोशी]

कैसे हासिल कर सकते हैं ? प्रधानमंत्रीजी जब दौरे पर गई थीं तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेसवाले ही सबल और स्थिर हुकूमत दे सकते हैं, लेकिन मैं बार-बार यह कहता रहा हूँ कि यह नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि आप कांग्रेस की नेता हैं, बल्कि जो उथलपुथल आज अपने देश में है, जो अस्थिरता है, वह अंगभूत है, आर्थिक दृष्टि से देखिये, सामाजिक दृष्टि से देखिये---यह इन्हैरेन्ट है। इसको कैसे दूर किया जाय, यह हम लोगों को सोचना चाहिये।

हम लोगों ने जब आज़ादी पाई और आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन दिनों, उपाध्यक्ष जी, आप भी हम लोगों के साथ थे—हम सब लोग कहां जाते थे ? ठीक है आप अब हमसे अलैहदा हो गये हैं, कोई बात नहीं है। गांधीजी ने एक जगह कहा है।

"If you have to follow the path of truth, sometimes even blood brothers may have to part."

जिसको जो रास्ता अच्छा लगेगा, वह उस रास्ते पर जायगा, इसमें मुझे कोई दुख नहीं है, मगर राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अन्त में जो कहा है कि "इस तरह से ही हम जनसाधारण की सेवा कर सकेंगे और इस विशाल गणराज्य की जिन महान पुरुषों ने नींव रखी है, उनके वचनों को पूरा कर सकेंगे।" महान् पुरुषों ने कुछ वचन दिये हुए हैं। हम लोगों ने जनता को क्या वचन दिये थे। आज अगर हम लोग राजनीति में लड़ते-झगड़ते हैं, तो इसका कारण भी यही है कि हमें दिये हुए आश्वासनों को पूरा करना है। जब हम जवान थे, लोगों के सामने जाकर कहते थे कि हम ब्रिटिश हुकूमत को यहां से हटाना चाहते हैं ताकि हमारे देश में जो गरीब हैं, उनकी गुरबत को खत्म करने का रास्ता निकल सके, हमारे देश में जो सामाजिक विषमता है उसको दूर कर सकें, इसलिये तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, हमारे साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हो, जेलखाने जाओ, लाठी खाओ, गोली चले तो हुतात्मा बन जाओ, लेकिन आज़ादी हमको अवश्य प्राप्त करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह उथल-पुथल सिर्फ भारत में ही नहीं है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, यद्यपि वहां की सरकार हमारे खिलाफ़ है मगर वहां की जनता हमारी दुश्मन नहीं है वह जनता जो उन दिनों में हमारे साथ थी, उसका बहुत सारा अंश हमारे साथ था, बादशाह खां हमारे साथ थे, अयूब खां के खिलाफ लड़ने वाले मुजीबुर्रहमान साहब भाषानी साहब, बादशाह खां के लड़के वली साहब, ये सब हमारे साथ थे, इन सब लोगों के साथ हमने हमारे भारत और पाकिस्तान की जनता को एक आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन को हम पूरा नहीं कर सके, वहां भी पूरा नहीं कर सके मुझे दुःख है कि वहां भी इतनी ही उथल-पुथल हुई है। मगर वह लड़ रहे हैं अपने लोकतन्त्र के लिये।

हमारे यहां बहुत सारे लोग ऐसे ही मजाक में कह देते हैं कि इस देश में तानाशाही होनी चाहिये। जब पाकिस्तान में अयूब साहब पावर में आये तो लोगों ने कहा कि देखो, इन्होंने करप्शन को कैसे हटा दिया। मगर आज आप देख रहे हैं कि वहां भी लड़ाई जारी है। अयूब की हुकूमत एक फौजी हुकूमत है, इन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनको लोकतन्त्र की कीमत मालूम है और यही कारण है कि जो तानाशाही आज वहां चल रही है, उसके खिलाफ़ वहां के नौजवान और जनता के नेताओं ने अपनी लड़ाई जारी रखी है और मैं उनको बधाई देता हूँ। जो लोग वहां शहीद हो गये हैं, खास कर वहां जो विद्यार्थी शहीद हुए हैं, नौजवान शहीद हुए है, उन्होंने बहुत

कुछ काम किया है। मैं उन तमाम शहीदों का अभिवादन करता हूं, क्योंकि वे लोकतन्त्र के लिये लड़े हैं।

जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, तो पड़ोसी को भाई की तरह रहना चाहिये लेकिन यह भाई-चारा कैसे पैदा हो सकता है जब कि वहां तानाशाही और यहां लोकतन्त्र का प्रयोग चल रहा है। अगर वहां लोकतन्त्र कायम हो जाता है, तो दोस्ती का रास्ता खुल जाता है, इसलिये मैं उनको बधाई देता हूं। मगर, उपाध्यक्ष महोदय, हमको इसकी जड़ में जाना चाहिये, आखिर जनता नाराज क्यों है, यह असन्तोष क्यों है, स्टेबिल्टी कैसे आयेगी। जब मैं इस पर विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो-तीन कारण हैं। एक कारण आर्थिक है। दूसरा कारण सामाजिक है और तीसरा कारण है राजनीतिक। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हमारी हुकूमत 20-22 साल में बहुत परिवर्तन लाई है, हम हर एक क्षेत्र में परिवर्तन लाये हैं—आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में तो हम परिवर्तन देख ही रहे हैं। . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : कांग्रेस में भी हुआ है।

श्री एस० एम० जोशी : राजनीतिक का मतलब ही वही है। अब आर्थिक दृष्टि से, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जनता से क्या कहा था—आजादी के पहले क्या कहा था और आजादी के बाद क्या कर रहे हैं? आजादी के पहले हमने कहा था कि हम गुरबत के साथ लड़ाई लड़ेंगे, आजादी के बाद हमने यह भी कहना शुरू किया—हम गरीबी के साथ युद्ध-स्तर पर लड़ेंगे। इसके लिये हमने पंचवर्षीय योजना बनाई, उसका मकसद हमने बनाया, उसमें चार बातों को अपने सामने रखा—1. हमारी राष्ट्रीय आय बढ़े, 2. हमारे मेहनतकश मजदूरों का जीवन-स्तर ऊंचा हो जाय, 3. गरीबों और अमीरों के बीच की जो खाई है, वह कम हो जाय, और 4. इस देश में जो बेरोजगारी है, उसको खत्म करें, खत्म तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसको कम करें। ये चार बातें हमने तय कीं, लेकिन उनमें से कौनसा मकसद हमने पूरा किया?

क्या अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो गई? बेरोजगारी कम हो गई? बेरोजगारी तो रोजाना और बढ़ रही है। आज हमारे 56 हजार इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। तकनीकी माहिर भी बेरोजगार हैं। बड़े-बड़े कारखाने बन्द हो रहे हैं। ऐसी हालत में लोग क्या सोचेंगे? यहां ऊंचे जीवन-स्तर को और ऊंचा करने की बात चल रही है लेकिन क्या मेहनतकश मजदूरों का जीवन-स्तर ऊंचा हो रहा है? मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस देश में जो पंचवर्षीय योजनायें चलाई उनको हमारे देश की गरीब जनता ने अपने खून से चलाया है। मैं जब कभी किसी देहात के क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं कि जाड़े के दिनों में लड़के और लड़कियां बैठे हैं, उनके तन पर कपड़ा तक नहीं है। उनको देख कर मुझे ऐसा लगता है कि हमने इन पंचवर्षीय योजनाओं में इन बच्चे और बच्चियों को जाड़े के दिनों में कपड़ों से भी वंचित किया है। नौकरी की बात तो अलग रही, हम उनको झोपड़ी तक नहीं दे सके हैं। लेकिन हम उन लोगों से इनडाइरेक्ट टैक्सेज ले रहे हैं। उसके अलावा नोट भी छपवाते हैं जोकि एक तरह से इनडाइरेक्ट टैक्स ही होता है। इस देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या तकरीबन 25 लाख होगी। इस देश में मैं समझता हूं एक करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए हम कह सकते हैं कि उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। वह वर्ग महाजन लोगों का है। दूसरी तरफ गरीब जनता है जिसको कि महाराष्ट्र में कहा जाता है कि वे बहुजन लोग हैं। इस तरह से 50 करोड़ में से एक करोड़ तो महाजन और 49 करोड़ बहुजन हैं। केवल एक करोड़ लोगों का जीवन-

[श्री एस० एम० जोशी]

स्तर ही ऊंचा जा रहा है। जब हमने हड़ताल की तो हम से कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? हम तो यही कह रहे थे कि सन् 47 में जो मजदूरी हमको मिलती थी, क्या उसको पाने की भी हम योग्यता नहीं रखते ? क्या आप हमारी मजदूरी उससे भी कम करेंगे ? एक समय यहां पर चर्चा हुई थी, मुझे तो उस समय यहां बैठने का सौभाग्य नहीं था, कि इस देश में जो राष्ट्रीय आय बढ़ी है वह कहां गई ? उसका पता लगाने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की जाये। हम तो चाहते हैं कि फुल न्यूट्रलाइजेशन हो जाये ताकि जीवन-स्तर बढ़े। नीडबेस्ड मिनिमम वेज दी जाये, आप फौरन दीजिए तो कम से कम यह मामला पंचों के सुपुर्द कर दीजिए, वे अपना फैसला इस पर दें। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। इसमें कहा है कि जो कम्पलसरी आर्बिट्रेशन है वही एक रास्ता है। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जो मुआहिदा आपने किया उसको तोड़ा जाये। जे० सी० एम० में आप लोगों ने एग्रीमेन्ट किया था उसके अनुसार सारा काम चलेगा। लेकिन वह नहीं हुआ। स्ट्राइक हुई लेकिन आज इतने दिनों के बाद भी हमारे 9 हजार मजदूरों को बाहर रखा हुआ है। कल मैं होम मिनिस्टर से पूछ रहा था कि जे० सी० एम० में बैठकर आपने जो फैसला किया, उसमें जो प्रतिनिधि थे, क्या वे वास्तव में प्रतिनिधिक थे ? कितने लोग उनके पीछे थे ? अंग्रेज लोग भी ऐसा ही किया करते थे। सन् 1930 में जब राउन्ड टेबिल कान्फ्रेन्स हुई थी तो कांग्रेस ने कहा था कि हम नहीं आयेंगे लेकिन तब उन्होंने और लोगों के साथ बैठकर फैसले किये। लेकिन क्या वे फैसले सारे भारत के फैसले थे ? कांग्रेस जो थी वह तो सारे देश का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरे लोग जो थे वह भी प्रतिनिधि थे लेकिन ज्यादा हकदार कौन था ? ज्यादा हकदार तो कांग्रेस ही थी। इसी तरह से आप लोग भी दूसरे लोगों के साथ बैठकर फैसला कर लें और फिर हमसे कहें कि हमारी बात मान लो, यह कैसे हो सकता है ?

उपाध्यक्ष जी, आज इस देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। रोज हम देखते हैं कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसी दशा में लोग अपनी जरूरतों को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं ? आज सारे देश में आर्थिक कारण से जो उथल-पुथल है वही हालत पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी दिन व दिन खराब होती जा रही है। दूसरा कारण जो है, जिस पर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं, वह है सामाजिक कारण। सामाजिक दृष्टि से हमने कुछ आश्वासन दिये थे जिसका जिक्र शिव नारायण जी ने अभी किया था। महात्मा गांधी कहा करते थे कि इस देश में एक भंगी को भी राष्ट्रपति होने का मौका मिलना चाहिए ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : शिव नारायण जी को बंगाल का गवर्नर बनाया जाये।...(**व्यवधान**)...

श्री एस० एम० जोशी : उपाध्यक्ष जी, यहां पर बार बार कहा जाता है कि हमने लोगों को आश्वासन दिया था कि हम सामाजिक विषमता को नष्ट करेंगे। ऊंची और पिछड़ी हुई जातियों के लोगों में जो खाई है और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए उच्च जाति के लोगों के दिलों में जो अप्रतिष्ठा की भावना है उसको समाप्त किया जायेगा। इस जहनियत को बदला जायेगा। मैं इसीलिए डिमोक्रेट हूं कि मैं समझता हूं कि इस जहनियत को बदलने का यही तरीका है कि हम खुद इस चीज को समझें। जब तक उच्च जाति के लोग इस बात को नहीं समझेंगे तब तक समाज में यह उथल-पुथल रहेगी।

उपाध्यक्ष जी, आयाराम और गयाराम की बात यहां सदन में बहुत चलती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नर्मदा के उस पार आयाराम और गयाराम की फसल क्यों नहीं होती है। कुछ थोड़ा सा उधर भी है लेकिन उतना नहीं है जितना कि इस तरफ है। इस तरफ क्यों है, इसका कारण मैं बतलाता हूँ। इसका कारण यह नहीं है कि उत्तर भारत की जनता का एखलाकी गिरावट हो गया है। आप स्वयं नर्मदा के उस पार के इलाके से आते हैं और आप जानते हैं कि अब वहां गवर्नमेन्ट में उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व नहीं है। इसी के कारण वहां पर कुछ स्थिरता है। हालांकि वहां पर भी अस्थिरता है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। समय कम होने के कारण मैं तफसील में नहीं जा सकता कि स्थिरता कैसे आ सकती है। लेकिन देश में इसके ऊपर अच्छी तरह से सोच विचार करने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ने यहां पर कहा कि हमसे सहयोग करो। लेकिन प्रार्थना करने से ही सहयोग कैसे मिल सकता है। मैं कहता हूं कि आपको इसकी जड़ में जाना चाहिए कि यह सब क्यों हो रहा है। मैं ममझता हूं उत्तर भारत में अभी वह सामाजिक क्रांति नहीं आई है। वहां उच्च जाति के लोगों को सोचना चाहिए कि इतने दिनों तक हमने हुकूमत चलाई, अब उन लोगों का जो प्रपोर्शन है और जो उनका मत है, उस हिसाब से उनके हाथ में सत्ता देनी चाहिए। सभी लोगों को इस बात के लिए राजी होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय बाहर के भी लोग आये हुए थे, ग्रेट ब्रिटेन के एक एक्स-मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्ट्री के, उन्होंने मुझसे पूछा था :

If you get Samyukta Maharashtra of your persuasion, do you think a Brahmin can become Chief Minister of that State ?

मैंने फौरन कह दिया—

"Not for 25 years to come."

25 साल तक नहीं होगा। संयुक्त महाराष्ट्र के माने यही हैं कि जो पहले राज्य था, उसमें जो पिछड़े लोग थे जोकि उच्च जाति के नहीं थे, जिनके हाथ में हुकूमत नहीं थी, वह उनको मिल गई। महाराष्ट्र के उच्च जाति के लोगों ने अगर कोई अच्छी बात की है तो वह यही की है।··· (**व्यवधान**)···

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज हम क्या देख रहे हैं। आज एलेक्शन्स कैसे हो रहे हैं ? लोगों की शिकायतें आती हैं कि आदमी लट्ठ लेकर खड़े हो जाते हैं और लोगों को वोट डालने नहीं देते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी जगह ऐसा हो रहा है। प्रत्याशी कत्ल कर दिये जाते हैं। फिर यह कैसे चलेगा ? अभी कल परसों हमारे पुराने मित्र श्री जयप्रकाश नारायण ने एक मीटिंग बुलाई थी, सभी पार्टीज़ के प्रतिनिधियों की। पंचायतीराज के बारे में चर्चा हुई। मुझे दुख होता है क्योंकि मैं एडवोकेट हूं डिमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का। श्री गायकवाड़ और मौर्या साहब ने कहा कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए लेकिन दरअसल बात यह है कि अगर उनको ज्यादा अधिकार दिये जांय तो फिर जो उच्च जाति के लोग हैं, जिनके पास मिल्कियत है, वे हावी हो जाते हैं और वे पिछड़े को न्याय नहीं देते हैं।

यह उनकी शिकायत है। यह आम लोगों को वोट देने का अधिकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा व प्राण है। स्वर्गीय डा० अम्बेडकर ने सन् 1930 में फर्स्ट राऊंड टेबुल कान्फ्रेंस के अवसर पर उधर के लोगों को अर्थात् ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा था कि भारत देश को आजादी देनी चाहिए और वह उसे दो साथ ही ऐडल्ट सफ्रेंज का अधिकार भी वहां की आम जनता को प्रदान किया जाय। हमारे गरीब लोगों के पास न जमीन है न प्रतिष्ठा लेकिन उनको वोट का हक़

[श्री एस० एम जोशी]

अवश्य दे दिया जाय। उन्होंने उस वक्त कहा था कि इस वोट के हथियार के जरिए गरीब भारत की जनता तरक्की करेगी। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? वोट देने का हर एक को अधिकार है लेकिन बेचारे गरीब लोगों को डराने के लिए और उनका वोट का हक खत्म करने के लिए लठैत खड़े करवा दिये जाते हैं। इस तरह से लठैतों से जो गरीब वोटर्स को आतंकित कराया जाता है उसके लिए मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं देता। बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह लाठी लेकर गरीब लोगों को वोट डालने से मना करते हैं क्या वह लोकतंत्र का खून नहीं कर रहे हैं? हर एक वोटर पूरी आजादी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल कर सके इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह की गड़बड़ के चलते यह हमारा पंचायती राज्य कैसे चल सकता है? अस्थिरता का यह दूसरा कारण है।

तीसरा कारण यह प्रादेशिक विषमता है और हुकूमत की तरफ से सवालों को फैसला करने में आना-कानी करना। अभी तेलंगाना प्रदेश के निर्माण के लिए आंध्र के लोगों ने कह दिया कि वह उसके समर्थक थे लेकिन आपस में लड़ाई क्यों हो गई? विकास का काम ठीक तरह से नहीं होता है। तेलंगाना की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और विकास में विषमता आती है।

इसी तरह बम्बई में शिव सेना की वर्तमान गतिविधियां ठीक दिशा में नहीं चल रही हैं। मैं मानता हूं कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए मैं जिम्मेदार हूं। यह सही है मैं संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में हिस्सा लेने वाला हूं। मैं उसके वास्ते जिम्मेदार हूं और जो गलतियां हो गई उनके लिए भी मैं अपनी जिम्मेदारी क़बूल करता हूं। वैसे हम लोगों ने उस वक्त भी बार-बार कहा था। हम जो राज्य चाहते हैं उसके माने यह नहीं है कि दूसरे इलाकों के लोग और दूसरी भाषा भाषी लोग महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे। वह रहेंगे और उनका और मराठी बोलने वालों का अधिकार यकसां होगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वह हम कर नहीं पाये। आखिर इसका क्या कारण है? मैं उस ओर सिर्फ इशारा करते हुए कहना चाहूंगा कि जो फैसले होते हैं वह जनता की सलाह मशविरे से नहीं होते हैं। महाजन कमिशन जब नियुक्त हो गया तब इस सवाल को लेकर जो लोग महाराष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे उनसे सलाह मशविरा नहीं हुआ। यहां पर बार-बार मैंने यह बात कही है। हुकूमत जब लोकतांत्रिक तरीकों की उपेक्षा करती है तब शिव सेना जैसी रीजनल शौवेनिज्म को बढ़ने का मौका मिलता है। वे रीजनल शौवेनिज्म को लेकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तब मेरे जैसे लोग जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं वह बेकार रह जाते हैं। फिर मामला उस तरह के शौवेनिस्ट लोगों के हाथ में चला जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों को हम जल्द से जल्द सुलझायें और जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं, सही मायनों में जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके पास बैठ कर यह मामले फैसल होने चाहिएं।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारे साथ सहयोग करें। राष्ट्रपति जी भी कहते हैं कि सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। बात उनकी ठीक है लेकिन सहयोग के लिए कुछ नीतियों की आवश्यकता है। आखिर उनसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं जिसके लिए कि हम यहां पर बैठे हुए हैं। हम पहले सन् 1948 तक कांग्रेस में थे और अब जब कांग्रेस से अलग हो गये तो हमारे नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए नहीं हुए। दरअसल नीतियों का हममें विरोध रहा, नीतियों को लेकर आपस में मतभेद रहा। हम कहते थे कि समाजवाद इस देश

में चाहिए और उन दिनों उन कांग्रेसियों ने कहा कि समाजवाद नहीं चाहिए। इस समय यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं वरना मैं बतलाता कि मुरारजी भाई के साथ तब हमारी इस बारे में बातचीत हुई थी। हमारा राष्ट्रीय सेवा दल जो कि एक कंस्ट्रक्टिव काम करने वाला संगठन था उसको करीब-करीब गैरक़ानूनी बना दिया गया था। मोरारजी भाई के साथ हमारी बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा कि आख़िर आप हमसे नाराज क्यों हैं और ऐसा क्यों किया गया? इस पर मोरारजी भाई ने कहा कि तुम्हारे लोग वहां जयप्रकाश नारायण की जय बोलते हैं और कहने लगे हैं कि वह समाजवादी हैं। मैंने कहा कि यह बात नहीं चलेगी और क्या आप इसकी गारन्टी दे सकते हैं कि आप आगे चलकर समाजवादी नहीं हो जायेंगे? अब वह कहते हैं कि हम भी समाजवादी हैं। लेकिन मेरा कहना है कि वह उनका समाजवाद खोखला रह गया है। दरअसल वह समाजवाद नहीं है और इसी कारण हम उनके विरोध में हैं। उनसे हमारी जाती दुश्मनी नहीं है जो कि हम विरोध में हैं। हम क्यों दुश्मनी करें? जब हम पर बेजा आरोप लगाया जाता है तो गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है। चूंकि हमारे मधुलिमये एक नौजवान हैं इसलिए उन्हें गुस्सा भी ज्यादा आ जाता है। मुझे भी आता है, लेकिन मैं गुस्सा बार-बार नहीं करता हूँ। हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि उनको देश की आजकी स्थिति में 20 लाख का नया मकान बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? चीज यह है कि हम लोग भी तो महात्मा गांधी की शिक्षा में पले हैं और हमारे उधर के मित्र भी उनकी उपासना करते हैं। "अनटू दी लास्ट" रस्किन की जो किताब थी और जिसको लेकर महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में वैसी हालत बने। देश में जब हम करोड़ों लोगों को घर नहीं दे सकते हैं तब हमारे लिए यह अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरीके से बड़े-बड़े आलीशान बंगलों में रहें। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेसी मंत्री लोग 500 रुपया प्रतिमास तनख्वाह लें। गांधी जन्म शताब्दी जब हम इस साल मनाने जा रहे हैं तब ख़ास तौर पर इस तरह की फिजूलखर्ची को रोकना चाहिए था। अगर बिलकुल इसे ख़त्म नहीं कर सकते थे तो फिलहाल अभी इसको मुल्तवी रखने में क्या नुकसान था? इसी तरह गांधी जी की जन्म शताब्दी को लेकर भी सरकार के द्वारा बहुत फिजूलखर्ची हो रही है। इस क़दर फिजूलखर्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो बड़ी-बड़ी किताबें छपवाई जाती हैं वह बेमानी हो जाती हैं जबकि देहातों में हमारे छोटे-छोटे बच्चों को खाना मयस्सर नहीं होता है। हम लोगों को इस हालत को ठीक करना चाहिए। आज देश में डबल स्टैन्डर्ड चल रहा है। दो नीतियां और दो दुनिया चल रही हैं। एक दुनिया महाजनों के लिए तो दूसरी दुनिया बहुजनों के लिए है। अगर वाक़ई यह सरकार पावरटी को बार बेसिस पर फ़ाइट करके देश से ख़त्म करना चाहती है तो फिर जाहिर है कि इस तरह से नये मकान बनाने की फिजूलखर्ची से बाज आना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम वार करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं तो क्या हम जनरल के लिए मकान बनाते हैं? जनरल को तो एक खेमे में बैठना पड़ता है, उसे धूप, सर्दी और बारिश में बाहर रहकर काम करना पड़ता है और लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए अभी हमें प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को अधिक सुविधाएं देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

जब आज बड़े-बड़े कारख़ाने बनते हैं तब पहले क्या बनता है? पहले बड़े-बड़े अफसरान के लिए ऐयरकंडिशंड मकान आदि बनाये जाते हैं। पहले वह सब चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन वह बेचारे मजदूर जो कि

[श्री एस० एम० जोशी]

उन कारखानों में काम करते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है। मैंने पूना कारपोरेशन को सुझाव दिया था कि उनके मास्टर प्लान में हर एक जगह जहां भी इंडस्ट्रियल ऐरिया बनें वहां 5-5 और 6-6 एकड़ भूमि मजदूरों के झोंपड़ों के लिए रिजर्व करदी जाये। अगर अब बड़े-बड़े कारखानेदार गरीब मजदूरों के लिए आवास का प्रबन्ध नहीं करेंगे तो आप ही बतलाइये वह हमारे बेचारे गरीब मजदूर कहां जायेंगे? अब शिव सेना के लोगों द्वारा उन बेचारे गरीब लोगों के बम्बई में बने हुए झोंपड़ों को जलाया जाना अनुचित बात थी। अब बेचारा वह केरल वाला आदमी अपना घरबार छोड़कर इसलिए बम्बई में नौकरी करने आता है कि वहां उसका पेट नहीं भरता और पेट की खातिर वह इतनी दूर बम्बई में नौकरी, मजदूरी करने के लिए आता है। केरल वाले बेचारे गरीब मजदूरों की शिव सेना के लोगों द्वारा झोंपड़ियों को जलाया जाना एक सरासर ग़लत बात थी और मुझे उसके लिए शर्म आती है। संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में अगर किसी राज्य के लोगों ने हमारा समर्थन किया है तो वह केरल राज्य है। सभी और लोग हमें उसके लिए गालियां देते थे और गुंडा समझते थे लेकिन केरल राज्य ने हमारी उस संयुक्त महाराष्ट्र की मांग का समर्थन किया। इसलिए उनके साथ जो सलूक वहां पर किया गया उसके लिए मुझे बड़ी शर्म आती है।

मैं आप से कह रहा था कि यह दुहरी नीति चल रही है। मैं कोई जाती बात नहीं कहना चाहता हूं इसलिए प्रधान मंत्री जी इसे जाती बात न समझें। अभी एलैक्शन के सिलसिले में जब प्रधान मंत्री जी बिहार जाती थीं तो उनके लिए पूरा प्रबन्ध सरकार की तरफ से होता था। रुपया पैसा भी ट्रेजरी से ही खर्च होता है, लेकिन इसके विपरीत मांगने पर भी हम लोगों के लिए साधारण सी सहूलियत भी मुहैय्या नहीं की जाती है। मैं अपना ही केस इस बारे में बतलाऊं कि मैं एक विरोधी दल का अध्यक्ष हूं और मैंने दरभंगा के कलक्टर को टेलीग्राम दिये कि मैं फलां तारीख को रात को वहां पर आने वाला हूं और मुझे सरकिट हाउस में सोने के लिए जगह दे दी जाये। जब मैं वहां पर रात को साढ़े ग्यारह बजे पहुंचा तो मालूम पड़ा कि मेरे लिए जगह नहीं है। एक कमरा खाली था और उसमें ताला लगा हुआ था। जब मैंने उसकी बाबत पूछा कि ऐसा क्यों है तो बतलाया जाता है कि जो बड़े साहब होते हैं उनके लिए एक कमरा रिजर्व रक्खा जाता है। जब मैं बाहर बरामदे में सोने की कोशिश कर रहा था तो बम्बई के एक अफसर जो कि वहां पर ठहरे हुए थे उन्होंने मुझे पहचाना और उन्होंने मुझे एकोमोडेट किया। अब पार्लियामेंट के एक मैम्बर होने के नाते हमें भी कुछ आवश्यक सुविधा का अधिकार है या नहीं? जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो हमें कम से कम एक रात के लिये ठहरने के वास्ते कमरा तो मिल ही जाना चाहिए लेकिन वह हमारे लिए नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि यह दुहरी नीति चल रही है। यहां हम जब पार्लियामैंट में बैठते हैं तो यह सुझाव चल रहा है कि हम पार्लियामेंट के मैम्बरों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए और जो हमारा डी० ए० है वह भी बढ़ाया जाना चाहिए।

क्यों भाई, उस वक्त आपको खेतिहर मजदूरों की बात याद नहीं आती? जब हम नीड-बेस्ट मिनिमम बेज मांगते हैं तब खेतिहर मजदूर की बात याद आती है, गरीब की बात याद आती है। ऐसी स्थिति में यह दावा नहीं रहना चाहिये कि हम वार फूटिंग पर पावर्टी से लड़ रहे हैं। यह दोहरी नीति चल रही है। जो महाजन लोग हैं उनका फ़ायदा होता है और जो बहुजन हैं उनकी बात नहीं होती।

15. hours

एक माननीय सदस्य : बहुजन के प्रतिनिधि हैं ।

श्री एस० एम० जोशी : इसी लिये तो मैं लड़ता हूँ ।

अब आप कानून की बात देखिये । क्या कानून का फायदा गरीब को मिलता है, देहात में जो गरीब आदमी पीटा जाता है उसको कानून का फ़ायदा मिलता है ? नहीं मिलता । जो शहरों में रहते हैं जिसके पास रुपया पैसा है, जो चिल्ला सकता है, पेपर वाले जिसकी बात कहते हैं उसको मिलता है । हमें कुछ नहीं मिलता । **आई एम स्पीकिंग फार दि क्लायेंट,** हम लोगों को नहीं मिलता । जब तक यह दोहरी नीति खत्म नहीं होती, तब तक यह जो स्ट्रगल ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जायेगी वह और बढ़ेगी । इसलिये जो उथल-पुथल है उसको दूर करने के लिए रास्ता बनाना होगा । रास्ता क्या होना चाहिए ? आपकी नीति में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिये ।

जो कुछ बम्बई में हुआ, मैं कहता हूँ कि उसके लिये एक एन्क्वायरी कमिशन होना चाहिए । और इन्क्वायरी कमिशन से उसकी जांच कराई जानी चाहिये ।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आज कल विक्टिमाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है । हमारे अधिकारीगण, कांग्रेस के मित्र और श्री यशवन्तराव जी भी कहते हैं कि जो कानून तोड़ेगा क्या उसको सजा नहीं दी जायेगी ? इसमें विक्टिमाइजेशन क्या है ? मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जिन शिक्षकों ने बहुत कामयाबी के साथ अपनी लड़ाई लड़ी, गैर-कानूनी स्ट्राइक में हिस्सा लिया और 35 दिन तक लिया, उनको तो आपने छोड़ दिया, लेकिन दूसरों को आपने सजा दे दी । एक ही गुनाह दो आदमी करते हैं, एक को सजा और एक को सजा नहीं, यह विक्टिमाइजेशन नहीं है तो फिर क्या है ?

एक माननीय सदस्य : उन्हें भी सजा दी जायेगी ।

दूसरे माननीय सदस्य : दोनों को छोड़ो ।

श्री एस० एम० जोशी : मैं कह रहा हूँ कि दोनों को छोड़ो । क्या हमने कोई गुनाह किया है ? अगर गुनाह किया है तो तुमने किया है । हमारे साथ जो वादा किया गया था उसको तोड़ा गया है । हमने कानून तोड़ने के लिए कुछ नहीं किया था, सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए किया था । इसके लिये विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए ।

हमारे सामने बार बार कहा जाता है कि हमें सहयोग दो । कैसे सहयोग देंगे हम आपको । हमारे यहां के लोग आज दो सालों से लड़ रहे हैं, स्टैन्डिंग कमेटी के लिये कि स्टैंडिंग कमेटी को अधिकार दो । आज देश में बात चल रही है राष्ट्रीय हुकूमत की, एक नैशनल गवर्नमेंट की । **गवर्नमेंट आफ दि टेलेन्ट्स** की बात चल रही है । लेकिन वह हो नहीं सकता । सब लोगों का एक राज्य नहीं हो सकता क्योंकि नीतियों में टकराव है, लेकिन यहां पर जो लोग हैं वह सब जनता के प्रतिनिधि हैं, कम से कम उनका सहयोग वहां स्टेंडिंग कमेटियों में तो मिल सकता है । मगर बहुत से फैसले आप पहले ही कर लेते हैं । जैसे रेलवे मंत्री ने कहा कि हमने कोई भी दर नहीं बढ़ाई है, लेकिन 1. 3. 69 से उन्होंने 10 प्रतिशत फ्रेट बढ़ा दिया है, उसका फैसला उन्होंने बिना पार्लियामेंट से पूछे हुए किया । क्या यह सहयोग लेने का तरीका है ? हमसे आप कहेंगे कि हम आपके सहायक हों, लेकिन स्टैन्डिंग कमेटी जो बनी थी उसको आप तोड़

[श्री एस० एम० जोशी]

रहे हैं। लेबर के बारे में स्टेन्डिंग कमेटी बनी थी और यह कन्वेंशन था कि लेबर की स्टेन्डिंग कमेटी में जब तक चर्चा नहीं हो जाती तब तक कोई कानून यहां नहीं बनेगा, लेकिन मजदूरों के अधिकारों को कानून द्वारा छीन लिया गया। जो चीज बन चुकी थी उसको भी सरकार ने तोड़ दिया।

अब आप एजुकेशन कमेटी को देखिये। अगर स्टेन्डिंग कमेटी होती तो 35 दिन तक शिक्षक लोगों को अपनी लड़ाई न करनी पड़ती। 35 दिनों तक उत्तर प्रदेश के टीचर्स ने स्ट्राइक किया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आज तक डिग्री कालेज का स्ट्राइक चल रहा है।

श्री एस० एम० जोशी : आज कल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन से मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जो स्कूल आफ़ इंटरनेशनल स्टेडीज है, उसकी रिपोर्ट निकली तो मालूम हुआ कि उसके लिये पहले जो 15 लाख रु० की ग्रान्ट थी वह अब 10 लाख रु० कर दी गई है, बिना किसी से पूछे हुए। उनके डाइरेक्टर से भी नहीं पूछा। पूछें भी किस से, कोई स्टेन्डिंग कमेटी तो है नहीं, अगर स्टेन्डिंग कमेटी होती तो इस तरह से फैसला नहीं हो सकता था। जिसमें हमारे साथ विचार-विमर्ष नहीं, उसको आप लोकतंत्र कैसे कहेंगे।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे हजारों आफिसर्स इमर्जेन्सी कमिशन के हैं। यहां पर चर्चा चलती है कि उनको आहिस्ता से निकाल दिया जायेगा। क्या स्टेन्डिंग कमेटी में बैठ कर विरोधी दलों के साथ मिलकर रास्ता निकालने की तैयारी आप की है? आप यही कहते रहते हैं कि हमें सहयोग दो, सहयोग दो। मराठी में एक कहावत है कि "काशी सजावे नित्य वदावे" काशी को चलो, काशी को चलो, ऐसा कहते रहो नहीं गये तो कोई परवाह नहीं है। इसी तरह से कहते रहते हैं कि सहयोग दो। क्या खाक सहयोग दो। कैसे सहयोग हो सकता है? हमारी जो मांगे हैं उनको कोई सुनता ही नहीं है तब हमारे लिये रास्ता ही क्या है? जो गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर ज्यादती होती है वह उसके खिलाफ लड़ते हैं। उन्हें शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक तरीके से सहयोग देकर उनका मार्गदर्शन करना यही हमारा काम है। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। मगर मुझे लगता है कि तब तक यह उथल-पुथल खत्म नहीं होगी जब तक जो देश का सन्तुलन आज खत्म हो रहा है उसको उच्च स्तर पर दुबारा ठीक नहीं किया जाता। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक देश में स्टेबिलिटी नहीं आयेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिहार में स्टेबिलिटी है, उत्तर प्रदेश में स्टेबिलिटी है, हरियाणा में स्टेबिलिटी है? कहां है। आपने यह किया है कि स्टेबिलिटी देते देते स्थिति को ज्यादा अनस्टेबल बनाया है। मैं गुस्से से नहीं कहता हूं, लेकिन आप को बतलाना चाहता हूं, कि जब तक आप जड़ में नहीं जायेंगे तब तक गरीब और अमीर के बीच का टकराव चलता रहेगा और मेरे जैसे लोग गरीबों की सहायता करते रहेंगे।

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Motion of Thanks to the President for his Address.

My hon. friend, Mr. A. K. Gopalan, started with the students' problem. He said that students are frustrated and, later on, he amplified that there is the question of unemployment leading to greater unrest. Many opinions are given for students' unrest. Some say that there is not sufficient contact between the teachers and the taught and some stress the question of unemployment. But I wish to draw your attention to the fact that if that is so, why there is so much of unrest in the affluent world. It is a world phenomenon and, if it is a world phenomenon, it has to be understood in those terms. Some

rational explanation has to be given for this world phenomenon.

I think, the students today, in the twentieth century, are functioning under a special psychological impact and the reason for that is that our environment has changed much. Uptill now, specially after the Industrial Revolution, there has been a conflict between science and religion and between science and dogmas and so on. So far, they have succeeded in the nomination of science over dogmas. We have also succeeded in having democratic forces, having sway over feudalism. Now, there has been some qualitative change and that qualitative change is the existence of atomic energy. It might appear farfetched. But I would like you to kindly consider that. The atomic energy has made it possible not only to destroy the world but also to build cities in the middle of the ocean and, in space, even to land on the moon.

It is achieving those things which were not conceived as possible even in imaginary writings and novels. Therefore, while from the time of Upanishad to the present day the realm of thought was considered beyond definition, today under the present atomic energy sway the realm of achievement is beyond description. There is a great deal of difference between the two. This concept creates certain psychological impetuses, certain psychological moods, and this has to be understood. We are changing our attitudes towards religion, towards political institutions, towards political philosophy and so on. Why ? It is because of this vital qualitative change in our environment; it is because all these institutions, and even religion, were born in an evironment which is foreign today, which is different today, to our environment. Therefore, the question is going on, and the student community feel it instinctively; there is a resistance, there is a desire for change; it is inherent in the situation; they do not know why; they do not know 'for what', still it is there; just as an animal in a forest feels instinctively the approach of a prowl, the youths of today are feeling the same approach and are reacting to it. Therefore all those who want to solve this question of student problem in 19th Century or early 20th Century terms are bound to fail.

Society is never ahead of time. It has to be pulled up and pulled out from certain situations. If there is the need for change which the student communiy or the youth do not follow it does not affect us because we are in the passing phase; it does affect them because they are young—and if you accept this hypothesis, then the only way to channelise these new urges is not by giving a few ministerships to some young men here and there; in order to channelise the urges, we must get the whole current and see that it mixes with the main-stream. That can be done if you decrease the age for voting from 21 to 18 years; then the politicians and statesmen will come in direct contact with that age-group, which is vital and which is important. If you want so draw up this vital and new force, this is the only way. It might look that we are bringing children, that 18 seems to be a very young age. But I would like to say that today boys and girls mature much earlier than what they used to do in our time, they are far maturer today; a boy of 18 years today is far more mature than a boy of 21 or 22 twenty years back. Therefore, from that point of view also it would be to our advantage to consider this. Therefore, I submit that this House might consider this proposal and the reasons behind it.

Another point that Shri A. K. Gopalan stressed was about agricultural production. He was not satisfied with the figures given by the President in his Address. Statistics is a peculiar thing. It can be moulded and can be altered and made to serve more than one purpose. Therefore, it is quite possible that the view that my hon. friend is taking from the position where he stands it different from the view taken by this side on the same question. That apart, I would have like to ask him one thing. In his whole speech he has been condemning Government and saying that all that has been stated in the Address is a tissue of lies misstatements and so on; he has said that the industrial progress is not very good and that agricultural production is

[Shri Bakar Ali Mirza]

not what it is stated to be and so on. But he does not say what we should do. For, after all, the year that has gone has gone. Now, we are planning for the year ahead. What does he propose that Governmhnt should do so that at least next year things could be better ? But there was not a word on this in his whole speech.

He was talking about agrarian revolution. I welcome this change, for, after all, if we increase the earning capacity of the agricultural sector, we get more in return than by increasing the earning capacity of the industrial or commercial sector, because in the agricultural sector, the number of people involved is large, and a small change means that we have to multiply it by millions. Therefore, it is very important that we stress on agricultural development. But I submit that the green fields would have been greener still it they had been fertilised a little more by land reforms. I thought that at least Shri A. K. Gopalan would mention that. We have been saying this over and over again but we have ignored it in practice. Last year, while replying to the debate on the Demands of his Ministry, Shri Jagjivan Ram had said that land reform was important and it should be attended to and looked after. I suppose this year also he will say the same thing and will continue to say the same thing. Probably all we can do is to accompany him chanting all the time *Ram Ram sath hai* After all, even American experts have advised us to introduce land reforms. They have introduced it in Japan and in Formosa. But here we are proclaiming a socialistic pattern of society as our aim and yet we cannot squeeze these little land reforms in that pattern. If agriculture is to be more prosperous; then land reform is a must.

About the industrial sector, there is, of course, some improvement in exports, but we have also to take into account devaluation. If you do that, the picture is not so bright. Anyway, if you want prosperity in the industrial sector, we have to accept some kind of automation and also computerisation. I know I am treading on an unpopular area in advocating this course because most MPs, specially labour laders, contend that it will lead to unemployment. But let it be remembered that the same thing was said by labour leaders when the industrial revolution started. They threw stones and wrecked factories, machines and so on accusing them as the biggest enemy of labour. But it was found that it was the same machines which proved the biggest friend of the labour class.

Therefore, today also if you want to compete in the world, you must have the most efficient system of production. Then the countries new in the field have got an advantage in switching over, because the old countries have got their own old factories and machines and they have to scrap them all and put in new ones. Whereas we are starting afresh and can take advantage of the latest advances made in the field. Hence automation and computerisation is a must if we want progress in industry.

Take, for example, the data lying there more than 100 years unprocessed in the Dehra Dun Forest Research Institute. With their present equipment, the statistics research department will take years and years to process them. But this can be done in a few months' time by applying these latest techniques and the knowledge gained can be applied to advantage all round.

There is also another advantage. It shows which is the most economical way of doing a thing. You have only to feed the machine with data concerning the two things. It will tell you which is the more advantageous course to adopt.

Let us decide as a compromise that all the export industries will be equipped with the latest automation, machines and computers, for our internal consumption industries, we use the old type of machinery. I go further and say. Let all the factories, say, cotton mills, be equipped with auto-

matic looms and automatic spindles, and let khadi only be utilised inside the country. This will give employment to millions. But they are not ready to accept that. They do not want to go one extreme or the other, but want to stay put. This is not a very healthy state of affairs.

In conclusion, I want to say this—and I do so with a great deal of pain. Our relationship with China is not good, is not as it should be. What it should be in future is a question of foreign policy which I am not touching now. But apart from that, there is the question of development. We were far ahead of China in 1945. We negotiated the transfer of power; of course, there was bloodbath, Communal riots and all that. But there was no destruction of property. China went through 20 years of war; the country was ravaged. But today after 20 years, they are manufacturing the hydrogen bomb. Through their exports, they have wiped out their foreign debt, paid every pie of it.

But what is wrong with us that we have accumulated aid to the tune of Rs. 6000 crores, on servicing which alone we have to pay Rs. 300 crores annually ? Why is it that our position is not so good as that of China in this respect ?

Today the Chinese are respected more than the Indians. Therefore, I ask the Government to ponder seriously why we are in this way.

Lastly, if we are to progress as my hon. friend Mr. Joshi said we have to make sacrifics and we hove to take up a position in which we have ways to indicate to the common man and so let the path of austerity be our guideline. Let all Ministers, as Gandhiji advised, take up small houses. There is the Rashtrapati Bhavan for inviting foreigners and holding banquets and so on. This idea of high and low should disappear. It is only when we identify ourselves with the common man and when he sees that we are also suffering, he would offer his cooperation and he will also sacrifice.

Today smuggling is going on and every conceivable thing is available here. Our bazars in Bombay and Delhi are packed with goods, more than the biggest bazars in the Soviet Union. Go to Moscow; you will not get many of the consumer goods that you get here, such as the transistor, foreign blades, etc. Why should it be like this ? I am glad that the Deputy Prime Minister has taken some steps to check smuggling and I wish him all success.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna): The President's speech, as usual, is an exercise in futility. He has done one thing; he has reminded us that this is the year of Gandhi Centenary. And many ideas and ideals come to our mind. Did it occur in this year to his Government that he need not traverse the great distance of half a mile in a mediaeval carriage drawn by six or four horses ? Has this anything to do with modernism ? Has it anything to do with science about which we boast ? Has it anything to do, above all, with our dignity as Indians ? I remember Mountbatten, when he ceased to be the representative of the King Emperor, telling us that as a representative of the people—because we had appointed him as Governor General—he did not think it necessary to live in that palace. He wanted to live in Trimurthy House. But our Jawaharlal told him that there was no need for that because 'you will be here for four or five months more.' That meant that after four or five months that house would be used for the purpose for which Gandhiji wanted it to be used. Women are generally more conservative. One day Lady Mountbatten told me: Mr. Kripalani, this is a beautiful palace; see that it is not turned into a hospital but it is turned into a museum. Today, Rashtrapati Bhavan is managed as a township. It has got all the arrangements that a town has—cinema hall and everything.

Is that necessary ? It may have been necessary for those who wanted to rule over us. They wanted to impress us with their pomp, with their glory, with their powers. Does our President, Rashtrapati, want to impress upon us his might ? His might is that of the people, and why should he or the Governors live in houses where our rulers lived ? They are not ruling they have to

[Shri J. B. Kripalani]

perform only formal and ceremonial functions. Why should they live in a more costly buildings and more grand style than those who actually conduct the Government ? Why cannot our Rashtrapati live even as our Prime Minister lives ? She is not living in a very poor and dilapidated house. The expenditure on her house is not negligible. Why can't the Governor in a State live as a Chief Minister lives ? Should we make ourselves ridiculous by adopting these foreign customs ?

I was at a table of one of these dignitaries : believe it or not : the lady, an old-type woman, was sitting at the table and instead of using a fork and a knife, she was using two forks ! Why should we make ourselves ridiculous. Even if the Rashtrapaty has got to keep some kind of digniti, let it be the dignity of a Nawab, a Rajah; not of our rulers who terrorised over us for a couple of centuries. These reforms will give us so much economy. And then, when this fashion is set, other people will also follow the same example. Does the Government want, as it happened in the case of so many statues of the foreign satraps that were decorating our capital, that their heads be needlessly beheaded ? They could have removed them at once to a museum but they waited till these innocent peoples' heads were cut off : the faces of some of them were blackened. Why do you wait that somebody may go on a hunger-strike before the Rashtrapati Bhavan and say, "He shall not go from his house unless he goes in a motor-car ?" It will save him time; it will be more dignified; it will be more modern; it will be more fashionable, and it will not remind us of our slavery after 21 years.

Then, the Rashtrapati has talked of integration. I am afraid, Sir, this word finds expression in every meeting of ours; every reformer, every leader, talks of integration. Nowadays they talk of emotional integration. I see emotional integration is going on throughout the world, in every country, in every corner, in every house, at every place. You will find it in our poetry, in our music and song. You will find it even in the cinema music that we are forced to swallow : what is called film music. Are things to be done emotionally or are they to be done rationally ? I do not know who invented this stupid word of emotional integration.

It would be suspect if a thing were done under the stress of emotion. We are told by our great men that emotions are to be suspect. Let emotions be anywhere else, say, in poetry. Even Ghalib forgot his usual humour and has talked of emotional connections. I really cannot understand what you want to integrate. Even as England, France, Germany, China and Japan, we were a nation. But we were not politically a nation. This was a new idea which we got from modern times, which was introduced by the study of British and European history. This political integration was emphasised by our fight for freedom. We had to resist somebody and we became united. That was natural. But unfortunately, after independence, we have not forgotten our old loyalties. Those loyalties were not to the nation, but first to the family, then to the caste, then to the religion, then to the region and so on. We had these loyalties and they have come to be revived. How did it happen ? Things do not get revived simply because some people wish it. They get revived because they are advantageous. If you belong to a particular family, you have a very great advantage. If you are a Member of Parliament and if you have got an orphan, he can occupy your place. If one happens to be a widow, she is given the husbands place. These family connections are paying. Caste connections are even more paying.

There was one ex-Chief Minister in one State, who could collect for his fifty-eighth or sixtieth birthday Rs. 60 lakhs in a couple of months. How could he do it if he did not belong to a particular caste ? Even our Prime Minister cannot collect Rs. 60 lakhs in a couple of months. There was another Chief Minister temporarily holding office. He ran as many candidates as there were seats—some 425 or so—and he succeeded. Wherefrom did he get the money ? He got the money from his caste people. They not only have money, but also

lathis. Both money and lathis were used. So, caste pays. Religion pays. Therefore, people take to them. Let these things be not paying. Let the law have its course. Let there be rule of law.

We have seen a horrible thing that has happened—widows and orphans getting into the places of their husbands and fathers. In UP something more outrageous was done. Because on account of some hitch the tickets could not be given to the men, so they were given to women. Whether the women were engaged in politics or not, whether they were in purdah or not, was not the question. They had to be given tickets, and they were given tickets. If we go on like this, are we going to have integration ? Repeatedly it is said that all parties must help in this integration. Yes, but even if all the parties help, this Government will not be able to bring about integration.

Integration will come only when there is rule of law. Our Constitution says that all the Indians are equal, they can reside anywhere, they can follow any profession and they can be in service anywhere. Why don't you put in practice the law ? These things that have happened in Bombay and in Andhra, why did they happen ? They happened because the authorities did not take action, did not move the law. We saw what happened in Naxalbari. As soon as the law moved, as soon as there was Governor's Rule, all at once the Naxalbari trouble disappeared, at least from the map of Bengal, it might have sulkingly gone somewhere else. If you administer the law properly, impartially and forcibly there is nobody who can break your law. If he breaks your law his neck must be broken. Unless you do that you cannot go on.

Long, long ago, some 18 to 19 years ago, when I was in the Congress I had told the Congress : "For God's sake rule or get out. If you cannot rule you have no right to spoil the good name of this measure and the good name of the freedom struggle which was started under Gandhiji." You talk of Gandhiji. The President reminds us of Gandhiji's Centenary. Everywhere prohibition has been prohibited. Not only prohibition is prohibited but, worse than that, every Government has taken to gambling. They have started what they call lotteries. It is horrible. Can any respectable government indulge in gambling ? If you do it can you blame the people for gambling day and night ? These are absurd things against which we have to guard.

How are our expenses increasing ? There are election funds. These election funds are collected by ministers. Fortunately or unfortunately there are ministers from every party. Is any account taken of them ? Do they render account to their organisation ? Do they render account to the public ? This is how our public life is managed and regulated.

What happened recently ? There was reshuffling of the Cabinet. The Congressmen will tell me, this is none of your business, this is our business. But if you do not make it your business it becomes our business it becomes the business of the House, because not only you have changed the ministers but you have changed their portfolios. Not only you have changed their portfolios but, what is worse, you have also split up the portfolios. On the eve of the budget you have done this splitting and, what they call, regrouping of departments. Are Congress people sleeping ? Do they doze during the day also ? I have a right to speak to Congressmen because I have been one of them and I love them yet. My Opposition friends say that I have a soft corner for the Congress. Yes, I have a soft corner for the Congress so I have a right to speak to them. Were they dozing when these things were being done ? Was the Finance Minister, who is considered to be a robust and independent person, sleeping when this was being done ?

Does he not know that the arrangement of the budget would be disturbed and the administration will have to work for 20 hours a day to put some arrangement into these disarranged affairs ? If the Prime Minister was so anxious to reshuffle the Cabinet, she should not ave changed the portfolios. Those who have been working for two years would have got some knowledge of the portfolios they were holding. One day I asked

[Shri J. B. Kripalani]

Dr. V. K. R. V. Rao—I do not know how many initials he has : but I suppose you understand whom I mean—what training you had in shipping. He did not reply here but in the lobby he said "Kripalaniji, you are right ; I had no knowledge of shipping ; but in these two years I have acquired knowledge." But when he has acquired knowledge you shift him to another department ; this is how you do things. For two years people have been doing something and they have acquired some knowledge. I know that they had no knowledge before. Because, it is said that the more ignorant a Minister is about the department in charge of which he is put, the fresher will be his mind as he will have no prejudices. Here my lady friend, Dr. Sushila Nayar, she had something to do with medicine and they found her inconvenient and pushed her out, because she could not bring a fresh mind. Her education was 20 years old and new doctors did not want her ; so, they shoved her off. That may be all right. But when they have learnt their business for two years, if you shove them off, it is a very strange !

It has also something to do with administration, because our budget is coming soon. I do not know in what shape and what form it will come. Perhaps, it will satisfy the Finance Minister; but it will satisfy nobody else.

Then, these Ministries are ever on the increase. There are, I hear, 56 Ministers. Believe me, I do not know who a Minister is. How can you recognise 56 people ? I do not know whether the Prime Minister herself would be able to recognise all these 56 people. Even if she is able to recognise them, I am sure she will not know in what department they are working. Every department has four or five Ministers. What do they do ? *Makhi Marna* ? Why are so many Ministers there !

Then there is another related question. A Minister wants a big paraphernalia—a Secetary, some Joint Secretaries, Deputy Secretaries, Under Secretaries, personal assistants, stenographers and peons and a big house to live in. When the British Government could do with five Executive Councillors, could we not do with at least 20 or 30 people ? Do we need 56 people ? How many Congress members are there in Parliament ? 283, out of which 56 are Ministers. So, one-fifth of them are Ministers.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): There are Ministers from Rajya Sabha.

SHRI J. B. KRIPALANI: There should not be any Ministers at all from Rajya Sabha. That is a misnomer. All right, if it is not one-fifth, it is one sixth; one-sixth of the Congress members in Parliament are Ministers. Is this not patronage ? *Kya yeh ghar ke bath hai* ? Is this doing business ? Can any business house go on like that ?

Then, there are, what they call, joint fronts, united fronts; God bless them. These United Fronts must satisfy every body.

There are 32 ministers in a ministry that is made yesterday in Bengal and afterwards they will add more. I am sure, here also there will be more additions.

People are thinking only in terms of ministers. They do not know that the minister has a big tail of employees behind him and all these have got to be paid and provided for.

Bengal has got only 13 districts. If we go by this, UP has got 52 districts. How many ministers should they have in UP ?

SHRI D. N. TIWARY: 52.

SHRI J. B. KRIPALANI: How can there be only 50 ? It will be at least 100.

AN HON. MEMBER: 110.

SHRI J. B. KRIPALANI: 110. Here is a mathematician. We are given a very rosy picture of what is happening in the country. The Rashtrapati should not have taken the trouble of giving us that. We hear it every day on the radio. We read of it every day in the press. What is new about it ?

As to the figures that they give, when it is convenient for a minister, he says that the figures are not correct. But they will always be throwing them in the face of the Opposition.

When there was depression and recession, whom did they blame ? They blamed the bad seasons. But when there is a little recovery, it is their work; it is not Indra who did it. Earlier Indra was unfavourably inclined towards us.

AN HON. MEMBER: Indiraji did it.

SHRI J. B. KRIPALANI: Oh ! Indira ? I was talking of Indra. I was talking of the male and not of the female.

15.52 hours.

[SHRI R. D. BHANDARE : *in the Chair.*]

Indra was very angry with us and there were two seasons of drought. All the calamities of the nation were due to these two drought years. Now there is a little recovery and we are told that this is all due to what the Government has done; that it is due to their good performance, a very glorious performance. It is a question of heads I win and tails you lose. Whatever may happen, this Government is always in the right. They have been given a God-given opportunity to misrule this country of ours. Even partial recovery is put to its credit.

There are many things about which I can talk, of which I would talk on some other occasion if the House can profit with whatever little advice I have to give. Please have some mercy on this country and have some regard for the person whose centenary you are celebrating; otherwise, let us not utter the name of Gandhiji. When people ask me to go and address them on Gandhiji, I say, "For God's sake, forget that old man; he is no more, why dig him up ?" Let us do our business as we like. But we will utter his name and do what we like. And what we like is not beneficial to the nation.

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कई समस्याओं का जिक्र किया है। भाषा का प्रश्न, साम्प्रदायिकता, नागालैंड का सवाल, वैदेशिक मामले, इन सारी बातों का उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। लेकिन आज देश के सामने अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह है गरीबी की समस्या। सारे सवालों की जड़ यह गरीबी की समस्या ही है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश की 80 प्रतिशत जनता एक रुपया रोज पर जीवित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत की पूरी जनसंख्या का तीसरा हिस्सा पूर्णत: गरीबी का जीवन बिताता है। पिछले बीस वर्षों में देश की आर्थिक उन्नति के बावजूद भी यह हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 रु० महीना और शहरी क्षेत्रों में 24 रुपये प्रति महीने की आमदनी पर जीवित है। प्रतिदिन एक रुपये से भी कम खर्च करने वाले लोगों की संख्या, जो 1952 में लगभग 80 प्रतिशत थी वह आज भी कायम है। सर्वेक्षण ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उसके अनुसार देश की पूरी आबादी का 34.3 प्रतिशत प्रतिमाह 15 से 24 रुपये की आमदनी पर निर्भर है। यह आज की आर्थिक परिस्थिति है।

राष्ट्रपति ने जो आर्थिक प्रगति का विश्लेषण किया है उससे आज की देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग है। दूसरा सवाल राष्ट्र की आमदनी का है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैरा 7, पेज 2 पर, गये वर्ष के मुकाबले में अब जो राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि हुई है, वह 1,393 करोड़ रुपये की वृद्धि बतलाई है। लेकिन महालनवीस कमेटी जो रिपोर्ट आई है उससे मालूम होता है कि यह जो राष्ट्रीय

[श्री देवराव पाटिल]

आय बढ़ी है उसमें, जो भूमिहीन लोग हैं या मजदूर हैं, वीकर सेक्शन आफ दि सोसायटी, उनकी इनकम बढ़ी नहीं है।

तीसरी समस्या बेरोजगारी की है। आर्थिक वार्ता से पता चलता है कि देश में बेरोजगारों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। खेती की पैदावार कुछ बढ़ी है और उससे खेतिहर मजदूरों को कुछ रोजगार मिला है। आज ही यह सवाल उठा था कि स्टेट्स की पर-कैपिटा इनकम क्या है। पंजाब भारत का एक सोभाग्यशाली राज्य रहा है लेकिन अब बेकारी की समस्या से ग्रस्त है। वहां भी बेकारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हाल की एक जांच से ज्ञात हुआ है कि वर्तमान आर्थिक वर्ष में पंजाब राज्य में बेकारों की संख्या बढ़ कर 4 लाख 18 हजार हो जायेगी। यही हाल महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में रोजगार तलाश करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1961 में एक स्थान के लिए औसत तौर पर 3 उम्मीदवार थे। लेकिन 1967 में यह संख्या बढ़ कर 4 हो गई है। विशेषतः शिक्षित समुदाय में बेरोजगारों की संख्या अधिक हुई है। यह समस्या केवल शहरों में ही नहीं देहातों में भी सुशिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ रही है। मैट्रिक और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की वार्षिक औसत वृद्धि दर 1961-66 के दौरान 21 प्रतिशत थी जो 1966-67 में बढ़ कर 18 प्रतिशत हो गई। 1961 में नोकरी तलाश करने वाले मैट्रिक और इंटर पास व्यक्तियों की संख्या 50,984 थी जब कि 1967 में यह संख्या 97,775 हो गई। यह अनुमान लगाया गया है कि चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में बेकारों की संख्या में और भी वृद्धि होगी।

तीसरा सवाल भूमिहीन मजदूरों का है। उनको साल में बराबर मजदूरी नहीं मिलती है। यही दशा खेतिहर मजदूरों की भी है। संसद ने प्रस्ताव मंजूर किया था कि योजना में भूमिहीन तथा खेतिहर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय और उन्हें न्यूनतम वेदन वेतन दिया जाय। परन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह रेजाल्यूशन पास किया गया था कि स्टेट और सेंटर इसके बारे में प्रोग्राम बनायें ताकि उनकी स्थिति सुधार लाया जा सके। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। मिनिमम वेज की तो बात छोड़ दीजिए, उनको साल भर मजदूरी नहीं मिलती है। जोशी साहब ने यहां पर नीड बेस्ड मिनिमम वेज की बात उठाई। खेतिहर मजदूरों के लिए नीड बेस्ट मिनिमम वेज भी नहीं मिलती है।

16.30 hrs.

दूसरा सवाल पुनर्वास की योजना के के बारे में था। यह तय हुआ था कि इनको मिनिमम वेज देने और साल भर मजदूरी देने के बारे में नवीन योजना बनायी जाय लेकिन प्लानिंग कमीशन या गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई।

इस तरीके से बेकारी की समस्या उग्ररूप पकड़ रही है। मैं छोटे किसानों की बात कहना चाहता हूँ। छोटे किसान पैदावार बढ़ा सकें ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है। कृषि का जो कार्यक्रम बना है उससे छोटे किसान वंचित हैं। अब जनता के प्रति जो गवर्नमेंट का कर्त्तव्य रहता है उसमें दो बातें प्रमुख रहती है यानी रोटी देना और रोजगार देना लेकिन वह इससे वंचित रहते हैं। इस तरीके से देश की जो जनता है जिसमें शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड कलासैज, खेतिहर मजदूर, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर जोकि अधिक तादाद में हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब व शोचनीय है। इसलिए देश के सामने सबसे बड़ी समस्या गरीबी की समस्या है।

मैं यह बात समझ सकता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद जो यह 30-40 करोड़ की है उसकी गरीबी को दूर करना कठिन है लेकिन एक काम कठिन नहीं है और वह यह कि उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उन्हें आप कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। वुडहैड कमीशन जो कि बंगाल के फैमिन के सम्बन्ध में बैठा था ऊसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है :

> "It was one of the obligations of Government to make available to every citizen basic quantities of food at reasonable rates, that making it available all over the country was a fundamental national obligation."

यह औबलीगेशन यहां पर संसद् में एक प्रस्ताव पारित करके हमने अपने ऊपर लिया था। मैं चाहता हूं कि यह जो गरीबी और शोषण को दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए था वह जो अब तक नहीं बनाया गया और जितना अच्छा बनना चाहिए था उतना अच्छा नहीं बनाया गया इसीलिए हमने इसका जिक्र किया है।

दूसरा एक सवाल मैं यहां पर कृषि का उठाना चाहता हूं। कृषि की नीति के बारे में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है। लेकिन एक बात मैं उसमें और बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि राष्ट्रपति ने अब की बार के अपने अभिभाषण में जिस का उल्लेख किया है उसकी बाबत वह अपने पहले भाषण में भूल गये। 63-64 और 64-65 में राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया और उसके बाद उन्होंने स्पीच के आखिर में कहा था कि अमुक अमुक बिल पेश किये जाने वाले हैं। एक साल के बाद दूसरे साल उन्होंने जो कहा वह बीमा योजना का उल्लेख करना था उन्होंने कहा था कि **क्रौप ऐंड कैटिल इंश्योरेंस बिलबी इंट्रोड्यूस्ड** लेकिन दुःख की बात है कि इस बिल का उसमें कोई जिक्र नहीं है। कृषि का जो कार्यक्रम आपने बनाया है, कृषि की प्रगति का जो कार्यक्रम है उससे पता चलता है कि यह सरकार कृषि के बारे में पीछे जा रही है और जिससे किसान को कुछ फ़ायदा हो ऐसी बात की ओर वह नहीं जाना चाहती है।

दूसरा उन्होंने जिक्र किया उचित मूल्यों का। मूल्य वृद्धि के बारे में सबेरे भी सवाल उठाया गया था कि मूल्य बढ़ रहे हैं। लेकिन मूल्य कौन सी वस्तुओं के बढ़ रहे हैं? मूल्य कृषि पदार्थों के नहीं बढ़ रहे है बल्कि गैर कृषि पदार्थों के मूल्य बढ़ रहे है। खेती की पैदावार जिस पर आम जनता जीवित रहती है वह जो अनाज का सवाल है तो अनाज के मूल्य नहीं बढ़े हैं लेकिन किसान को उसके खाद्यान्न के जो मूल्य देना चाहिए उसके बारे में सबेरे जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में सरकार की ओर से बतलाया गया कि किसानों के खाद्यान्न के मूल्य नहीं बढ़ाये जायेंगे। मैं इस सम्बन्ध में यहां पर बतला देना चाहता हूं कि कोई भी देश जो अनाज के बारे में स्वावलम्बी हुआ है वह किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य देने से हुआ है। जब तक इस देश में खाद्यान्न के उत्पादकों अर्थात् किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य नहीं दिये जायेंगे तब तक यह देश कभी भी स्वावलम्बी नहीं होगा। देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए आप को किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य देने पड़ेंगे और अधिक उत्पादन करने के लिए उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह बात गवर्नमेंट नहीं कर रही है। मैं मानता हूं कि सरकार ने गेंहूँ, चावल के लिए कुछ उचित मूल्य नियत किये हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि देश का एक बड़ा उद्योग है जिसको कि टेक्सटाइल उद्योग कहते हैं जिसमें कि मिल मालिकों के करोड़ों रुपये और लाखों मजदूरों का सवाल आता है तो किसान की जो कपास रहती है उस उत्पादित कपास की सरकार ने क्या मिनिमम प्राइस नियत की है? अब तक

[श्री देवराव पाटिल]

कपास की जिसे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं वह किसानों को नहीं दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कपास के बारे में आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय नहीं करेंगे तब तक किसान लूटा जाता रहेगा। इस तरह करोड़ों रुपये से किसान लूटा जाता है क्योंकि किसान के लिए कपास के बारे में मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ़िक्स नहीं की गई है। यह एक उसका कारण है जिसके कारण यह समस्या बहुत जटिल हो रही है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान एक शब्द जिसका उन्होंने उपयोग किया उस से मुझे दुःख हुआ। उन्होंने कहा कि कृषि का उत्पादन बढ़ने से यह समस्या खड़ी हो गयी कि किसानों को अपनी पैदा की हुई चीजों की मुनासिब क़ीमत मिले। उनके सामने समस्या हो गई। जब हमारा उत्पादन बढ़ता है तब किसानों को उनकी उपज की क़ीमत देने के बारे में गवर्नमैंट के सामने समस्या पैदा हो जाती है। मेरा निवेदन है कि इस तरीके से सवाल हल करने का जो ढंग है वह ख़राब है और इस से खेती का उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

कौस्ट आफ़ प्रोडक्शन अर्थात् आप ने जो उपज की प्राइस फिक्स कर दी है उसके बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल जो प्राइस उन्हें दी गई थी उससे अच्छी नहीं है और वही पिछले साल वाली प्राइस उन्हें दी गई है। लेकिन मैं कृषि के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कृषक को जो चीजें लेनी पड़ी उनकी पिछले साल क्या क़ीमत थी और इस साल उनकी क़ीमत क्या है? इसलिए राष्ट्रपति जी जो कहते हैं कि गये साल जो उन्हें क़ीमत दी गई थी वही आज दे रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। मैं सदन के मार्फत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस कौस्ट आफ़ प्रोडक्शन के बारे में कम से कम अपनी एक योजना तैयार करे। कम से कम उसका अभ्यास तो करे कि गेंहूं, चावल और कपास पैदा करने में उसे क्या लागत आती है। इन के उत्पादन करने में किसान को जो लागत आती है उसके मुताबिक ही किसानों को उनकी उपज की प्राइस मिलनी चाहिए। उसके मुताबिक अब अगर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलते हैं तो फिर हम और संसद बखूबी यह समझ सकेंगे कि भाई कौस्ट आफ़ प्रोडक्सन उनका यह पड़ता है और किसान को हम यह उनकी क़ीमत दे रहे हैं। इसलिए कौस्ट आफ़ प्रोडक्शन का पता लगाना और उसे जाहिर करना यह एक ज़रूरी बात है।

खेती के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन एक बात पिछले 20 साल से नेगलैक्टैड की जाती रही है और वह है ड्राई एग्रीकलचर। हुआ यह है कि ड्राई एग्रीकलचर को तो नेगलैक्ट किया गया है और इर्रीगेटेड एग्री-कलचर पर खूब अटैंशन दिया गया है। मेरे पास योजना आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें इस बारे में यह कहा गया है :

> "We have over the years neglected dry agriculture and concentrated attention on irrigated agriculture. We have built up structures—co-operative and other—that easily profit the substantial and the middling cultivator. But they do not look into the problem of the small farms and the landless labour."

जब तक यह पर एकड़ उत्पादन नहीं बढ़ता है तब तक खेती का उत्पादन सही तरीके से नहीं बढ़ेगा और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार को यह केवल सिंचित खेती के बारे में न सोच करके ड्रा फ़ार्मिंग के बारे में भी सोचना चाहिए।

दूसरा सवाल जो इस में आता है वह सिंचाई और बिजली का है। जाहिर है कि बिजली और सिंचाई बहुत ज़रूरी चीजें हैं। इस समय इर्रीगेशन मिनिस्टर यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपका पहले जो प्रोग्राम था और आज जो आप का प्रोग्राम है उसमें कमी हुई है या बढ़ोत्तरी

हुई है ? मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि बिजली और सिंचाई का जो प्रोग्राम कृषि के लिये था, उस में कटौती हो गई हैं, वह प्रोग्राम कम हो गया है। गांधी शताब्दी के वर्ष में, हम लोगों को बतलाया गया था, एक लाख गांवों में बिजली देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया ? अब कहते हैं कि उतने गांवों को नहीं दे सकते हैं। इस लिये अब 70 लाख गावों को बिजली देने का प्रोग्राम रक्खा गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐग्रीकल्चर के लिये बिजली और पानी देने का भी जो प्रोग्राम कबूल किया गया था, वह आप पूरा नहीं कर सकते हैं।

इसके बाद लैंड रेवेन्यू का सवाल आता है। इस देश में स्माल कल्टिवेटर्स हैं जिनके पास अनएकानमिक होल्डिंग हैं। उनकी पैदावार बहुत कम है और जितना खर्च करते हैं उससे कम उत्पादन आता है। आज आप उन से टैक्स लेते हैं। मेरा सुझाव यह है कि जो छोटे किसान हैं, जो अनएकानमिक होल्डिंग रखते हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये। प्लैनिंग कमिशन इसके बारे में सोच रहा है। जब छोटे किसान की पैदावार थोड़ी सी बढ़ी है तब वह लोग सोचते हैं कि किसानों पर इनकम टैक्स लगाया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जब आप के पास किसान का पूरा उत्पादन आ जाये तब आप उस पर इनकम टैक्स लगाने का सुझाव रक्खें। मैं पूछना चाहता हूं कि जो छोटा किसान है, जो खर्च ज्यादा करता है लेकिन उत्पादन कम पाता है, उसके लिये आपने क्या किया है ? उसकी लैंड रेवेन्यू माफ करने का जो सवाल है, उसके बारे में आप क्यों नहीं सोचते ? आज तो प्लैनिंग कमिशन का काम सिर्फ ट्रेडिंग रह गया है। उसका सारा नाम जो 30 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं, जो अच्छे आदमी कहलाते हैं, ऊँचे आदमी कहलाते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा है उनका खयाल करना है। बीस साल तक 70 प्रतिशत गरीब लोगों के लिये कुछ नहीं सोचा गया है। इन लोगों को कभी भी प्राधान्य नहीं दिया गया है। जनसाधारण का जो प्रश्न है वह कभी भी उनके सामने नहीं आया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि प्लैनिंग कमिशन का भी कुछ दायित्व है उन लोगों के प्रति। अन्न, वस्त्र, दवा आदि आवश्यक सामग्रियां उचित मूल्य पर सुलभ करना प्लैनिंग कमिशन का ध्येय होना चाहिये।

मैं बतलाना चाहता हूं कि आज प्लैनिंग कमिशन शहरी और देहाती लोगों में भेदभाव करता है। कोई भी सुविधा देने का सवाल हो तो भेदभाव से काम लिया जाता है। अगर शहर को पानी देने का सवाल हो तो शहर के लोगों से अनुदान नहीं लिया जाता, लेकिन अगर गांवों में कुंएं खोदने हों, तो उनसे पापुलर कंट्रिब्यूशन लिया जाता है। जहां तक मंहगाई भत्ते का सवाल है, जिस 80 प्रतिशत जनता की मासिक इनकम 40 रु० से कम है, उनके लिये कोई मंहगाई भत्ता नहीं है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गांवों में पीने का पानी, वस्त्र, मकानों के निर्माण की व्यवस्था, सड़कों में सुधार, बेरोजगारी की समस्या, छोटे किसानों को कृषि कार्यक्रमों में लाभ, इन सब बातों के लिये यदि आप काम करेंगे तो जैसा राष्ट्रपति ने कहा है, यह देश गांधीजी के सपनों को पूरा करेगा। लेकिन यह उसी वक्त हो सकेगा जब गांवों की कमियां पूरी हो जायेंगी।

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): I have gone through the President's Address to the joint session of Parliament with due care and caution and I find that it is only a haphazard ritual and a routine affair. It gives only the most uninspiring catalogue of the so-colled achievements of the Government. I do not understand why there should be a ritual like this President addressing the Parliament

[Shri Hem Barua]

or the State Governors addressing the State legislatures. This has become a ritual and we have maintained this ritual because tradition sanctifies it.

Possibly, the British monarch addresses Parliament, and therefor we in India follow the same pattern: that the President should address the Parliament or the State Governors should address the State Assemblies. But less and less attention is being paid to these Addresses. And there is trouble also over the Address. Therefore, my suggestion is that particular provision in the Constitution I know you are opening the pages of the Constitution...

MR. CHAIRMAN: Because that is the provision.

SHRI HEM BARUA:...that particular provision in the Constitution that enables the President to address Parliament or the State Governor to address the State Legislature should be amended and this provision should be eliminated from the Constitution altogether.

Sir, when you go into this Address given by the President to Parliament, you do not find any enunciation of the policy that the Government propose to pursue. Only it is a dry catalogue of events. Nothing more than that. Intellectually it is sterile; spirtually it is inept, and from the point of view of quality it is insipid. Why are you putting things like that. Do not the President or the State Governors have any other responsibility towards society ? They have many more things to do except addressing the Parliament or the State Legislatures.

There is a passing reference in the President's Address to improvement in agriculture, and agricultural production. But what percentage of this improvement is due to the governmental effort and what percentage is due to the bounty of Nature ? The Address is ominously silent about that. We are interested in knowing the percentage of improvement due to the governmental efforts. But it does not give us any idea about that. We forget the fact, and the Address also forgets the fact that only last year there was a massive drought in this country and a massive flood also that devastated our cultivation and agricultural production in Assam. What have you done ? In Assam, floods are an annual visitation; they destroy not only human population, but also cattle population and agricultural production. The monsoon batters the lands, and the riverss well, and the swollen rivers flow across the banks into the paddy land and destroy the crops. This is an annual feature, but what has been done by this Government to checkmate the menace of floods in the State of Assam ? Nothing has been done.

May I tell you that Assam is one of the most neglected States of India ? There is no doubt about it; and then, Assam produces crude oil, tea, jute and all these commodities, but Assam only gets a neglected attitude from this Government. That is what is happening. May I tell you, if things are allowed to pass like this, India will have to lose Assam one day. This is an ominous warning, and I am sorry to give this warning. But, at the same time, the facts warrant such a conclusion.

There is always an attitude of negligence towards Assam. For a river-bridge, you have to agitate; for an oil refinery, you have to agitate; for her due share in the finances, you have to agitate. Assam is neglected like this always, and I do not understand why it is neglected. There is nothing, no reference to the State of Assam in the President's Address. Assam has been reduced to the position of a guinea-pig in the laboratory of the Union Government where the Union Government have all sorts of stupid experiments. (*Interruption*). That is what the Central Government is doing. Assam has been reduced to the position of a guinea-pig in their laboratory. (*Interruption*) I say that Assam will go out of the Indian Union if things continue like this. I am sorry to say like this. But if things are allowed to pass like this, India will have to lose Assam one day and it will be a very sad and a tragic day.

There is no mention in this Address of the tottering condition of our economy. The *Economic Survey* is a pointer to the fact that Indian economy is in the doldrums. There is no doubt about it. What measures are taken to improve the economic condition of India? There is nothing, no indication, of policy or measures in that direction in the President's Address. There is nothing of the kind in the President's Address. The President's Address does not throw any light on these particular facts. But, at the same time, what happens ?

There is a passing reference to the violent activities in the country. It is almost like an obituary reference we make on the floor of the House to unknown persons who have died. Have we tried to examine the genesis of these violent activities and find out the reasons ? We find that Harijans have been massacred in different parts of India. There is only one reply to that. The caste Hindus of India are suffering from a psychology of arrogance. They think free India belongs to them and not to anybody else. That is why this newly won freedom has given them arrogance and they massacre the Harijans. We have never tried to analyse these facts.

The basic causes for these things are economic inequality, regional imbalance in industrial development, etc. There is no attempt to remove them. There is no mention of these basic causes in the Address at all. I do not understand what for we should have a President's Address if there is no mention of these things. There is regional imbalance and at the same time, the problem of unemployment has got intensified. During these 20 years, the figure of unemployed has gone to 58.2 per cent. That is why our young people are restless and they shout in the university convocation "We do not want paper degrees; we want jobs", because they are worried about their future. That is the pattern in our society and nothing has been done to remove these causes.

We condemn in the most ruthless terms the violent activities of Shiv Sena in Bombay and Lachit Sena in Assam. But the fact remains that these organisations have pinpointed the attention of Government to certain relevant basic facts of negligence, indifference, delay and the problem of unemployment. The Home Minister said, it is easy to condemn the Mizo hostiles sitting in this secluded place. I do not know whether he proposes to hold a session in Mizo Hills. It is easy to condemn these violent activities sitting in the secluded corner of this chamber. At the same time, why don't you probe into the causes of the unrest and remove them ? The President of the Congress Party, Mr. Nijalingappa, has made a very useful suggestion. He has demanded a judicial enquiry into the activities of Shiv Sena in Bombay. We should all support this demand.

Coming to international problems confronting us today, the Prime Minister goes about saying, we want to enter into a dialogue with China over the Indian territories forcibly occupied by China. On the other hand, the Deputy Prime Minister goes about saying, we will recover the territories under forcible occupation of China by force. Which posture is correct—the posture of the Prime Minister or that of the Deputy Prime Minister ? There is contradiction between them. What are we to believe ? Are we going to recover these territories in pursuance of the unanimous resolution adopted by this House by force of arms or are we going to have a dialogue, as the Prime Minister suggests ? The dialogue must also have a basis and formula. There are people in India who suggest that we should try to solve the problem peacefully by entering into a dialogue. But everybody is afraid of suggesting the basis of the dialogue. We had a dialogue with China even in Rangoon where our officials met their Chinese counterparts and produced a voluminous report justifying the cause of India with the help of maps, charts and other documents. I put a question to Pandit Jawaharlal Nehru whether China was going to accept this report or not. He said, let us hope and trust that there will be a change of heart so far as China is concerned. There has been no change of heart.

[Shri Hem Barua]

There was a talk about dialogue with China in season and out of season. The very fact that our officers had a dialogue at Rangoon and they produced a very voluminous report which was rejected by Pakistan shows that it is not right to have it. Now the danger to India is intensifying. It is getting more and more intensified. I do not say so because of thermo-nuclear power but because of portentious developments in Pakistan. General Ayub has expressed his desire to step down from his *gaddi* and Bhutto might come and occupy that *gaddi*. He is known for his prejudices against India. It was this man who said that they will fight for a thousand years—that man is not going to live for a thousand years—in order to recover Kashmir. He would try to persuade China to attack India again. Therefore, the portentious developments in Pakistan are too portentious for us because if in place of Ayub Bhutto comes then the danger to India from Pakistan gets more and more intensified. I know there is nobody in Pakistan who is pro-India and the surest way to destroy the image of a Pakistani leader is to say that he is pro-India. At once his image in his country gets liquidated, gets destroyed. I do not want to do that.

The fact remains that the unemployment problem is getting more and more intensified in this country and our enemies, China and Pakistan are aiding some of these hostiles in this country with arms and ammunitions.

AN HON. MEMBER : You want war preparations ?

SHRI HEM BARUA : I said that the Prime Minister's suggestion of dialogues weakens our defence and our will to resist. At the same time, Pakistan and China are having their agents working in a subtle way in this country. How could there be a *futwah* from Pakistan during the mid-term elections asking the people of India to vote for certain people ? We have to accept Pakistan as a foreign country. We have to accept China as a foreign country. There is nothing communal about that.

What is destroying the basic fabric of India today is this communal idea. This idea should be given a decent burial. Those people who think Pakistan is their country must also understand that Pakistan is not their country, India is their country and their basic loyalty should be to India to whatever religion a man or woman may belong.

The young people in this country are becoming restless only because of unemployment. We have neglected NEFA for a long time. There is restlessness with the result people from NEFA are being taken by China for training. We promised *panchayati raj*, a democratic organisation, to the people of NEFA. The President made a Proclamation to that effect as far back as in 1967. But nothing has been done about this.

We have neglected different parts of the country and there we invite all this trouble. When trouble comes we try to control it. It is not correct. That should not be the aim of the President's Address or the aim of the Government. I want to conclude by saying that the President's Address to Parliament is an exercise in futility which involves a lot of wastage of time, money and energy and, therefore, the Constitution should be amended to the effect that this provision that entitles the President to address Parliament and the State Governors to address the State Assemblies should be amended and should be completely done away with.

DR. MAHADEVA PRASAD (Maharajganj) : Sir, I rise to support the motion moved by my colleague Shrimati Sushila Rohatgi. Many of our hon. friends from the Opposition benches complained of shortcomings in the President's Address. Let me tell them that the President's Address is not a catalogue of events of history. It is surely not an annual report.

The President himself has said in his Address that it is "a realistic appraisal of the year under review and to delineate the broad features of Government's policies and purposes in the coming year".

The last two years were really worse periods of economic set-back, not only because of floods and drought but also certainly because of gheraos and *bandhs* for which our friends sitting opposite are to be given the credit. Because of the courage, fortitude and wisdom of our people, our country has not only come out of this but has moved on the road to economic recovery.

Shri Gopalan talked this morning of the futility of our plans. I would like to tell him that our planning is not on the Chinese lines, where they regiment and compel people to move in a certain direction over a certain period of time. We believe in democratic planning. We move the people not by compulsion but by persuasion and we expect them to participate in planning freely and voluntarily.

To quote one line from the Address of the President : "The milestones passed on the road to our economic recovery can be easily identified." Can anyone deny that there has been an upward trend in our agriculture ? Is it not a fact that the prices have relatively stabilised ? Has not our balance of payments position improved ? Could anyone say that the process of recovery in our industry has not begun ? I will here point out the agricultural production, which is the base of all economic development in our country.

I quite understand that Shri Bal Raj Madhok of the Jan Sangh could not give due credit to Governmental efforts in raising food production in the country. But I was at a loss when I heard my hon. friend, Shri Hem Barua, saying that he could not appreciate the governmental efforts in raising food production in the country. We know that in our State of Uttar Pradesh, when the SVD government was ruling the State, even though Shri Bal Raj Madhok's party men had a greater share in that government, his partymen in the State Government did not care to help the farmers. So far as our experience goes, not only did they not help the farmers but they put positive hindrances in their way. They discouraged the farmers, particularly small farmers, orjm making their contribution in raising food production in the country.

Do you know what they did ? As we all know, the main problem of our agriculture is that of irrigation. A State is expected to increase the irrigational facilities in its territory on its own as far as it can and otherwise also help the farmers by giving them grants, subsidy and loans and by extending electrical and other facilities. Under the Congress regime in Uttar Pradesh, if a farmer constructed a masonry well the government gave him 25 per cent subsidy, if he bore a private tube well he would have free electric connection up to a distance of four furlongs and if he had a pumping set worth Rs. 5,000 he would be given a subsidy of Rs. 2,500. All these facilities were stopped when Shri Tambeshwar Prasad of Jan Sangh became the Irrigation and Power Minister of Uttar Pradesh. In the mid-term elections the Jan Sangh leaders went round promising that if they are voted back to power, if they are returned, they would provide them water to every field and work to every man : "हर हाथ को काम और हर खेत को पानी" But the people did not believe their tall promises and cut them to size.

It is a fact that good rainfall always helps food production in our country. But it is unfair to minimise the contribution of the new strategy sponsored by the government. The increase in food production is due to the new strategy which includes use of high-yielding varieties of seeds, introduction of double and multiple cropping, extension of irrigational facilities and, above all, the price policy and the like measures adopted by the Government.

May I enumerate a few of them ? In 1967-68 it was possible to raise the area under high-yielding varieties of seeds to 6.03 million hectares and the target for 1968-69 is 8.5 hectares. Introduction of multiple cropping was attempted on 3 million hectares in 1967-68 and the target for 1968-69 is 6.1 million hectares. The programme of minor irrigation has been making steady progress since 1960-61 but has recently gained substantial momentum. Between 1960-61 and 1966-67, 754,000

[Dr. Mahadeva Prasad]

pump sets were installed, 98,000 private tube wells and filter points and 3,000 State tube wells were constructed. In 1967-68 alone, 2,48,000 pump sets were installed, 48,000 private tubewells and filter points and 100 State tube wells were constructed. In addition, 19,700 masonry wells were sunk. The additional area brought under minor irrigation in 1967-68 amounted to 1.38 million hectares. This benefit is to be extended to another 1.5 million hectares in 1968-69. Similarly, the pace of consumption of fertilisers was notably changed. It has increased from 13,82,000 tonnes of nutrients to 20,63,000 tonnes of nutrients in 1967-68 and the 1968-69 target is of 28 lakh tonnes of nutrients.

Therefore you will certainly agree when I say that the efforts of Government must be given due credit for the increase in food production of the country. This, combined with the hard labour of the people, bore fruit. But in this connection I must say that the steps taken by the Government for having increased production have not succeeded in achieving the social and economic objectives laid down in the Five Year Plans. We have largely depended on progressive, well-to-do cultivators for implementing the high-yielding variety programme. From a recent study in Saharanpur it is proved that cultivators having holding up to 5 acres participating in the high-yielding programme were only two whereas those having holding above 25 acres were 13. At Amritsar this figure was 1 and 26. The progressive cultivators really represent the upper strata of the rural society. While a socialistic pattern of society is said to be our goal, we are doing things which defeat the very purpose of a socialistic pattern. Government resources are being diverted for strengthening the financial position of the rich farmers in our country. This will only widen the income disparities. Therefore while implementing the new agricultural strategy, we should not lose sight of the human aspect of the problem and its related distribution aspect.

Nearly 70 per cent of the population is dependent upon agriculture and most of them are small agriculturists. There is no immediate prospect of transferring this large segment of our people to other economic activities, The responsibility of providing livelihood to this great bulk of our population will continue to be on agriculture. This is a hard fact. Any agricultural strategy, whether it is new or old, which does not aim at improving the lot of small cultivators will ultimately lead us nowhere. Even the aim of achieving surplus food production cannot be realised which is so necessary for our economic growth, unless production not only per acre but also *per capita* is increased. The All India Rural Credit Survey Report rightly remarks—I quote :—

> "Agricultural production in India depends upon millions of small farmers. It is their hard work and efficiency which will ultimately raise agricultural output. For want of funds, many of them are unable to use improved seeds and manures or to introduce new techniques. Some of them cannot even keep wells and tanks in good repair."

The Reserve Bank survey of co-operative credit has shown that only the top 28 per cent of the rural households drew more than 74 per cent of such credit. I know that it was felt that instead of spreading developmental efforts and resources throughout the country, the concentration be made in men and material and also in area. The immediate goal was to achieve rapid increase in agricultural production. But now the time has come that care should be taken not to widen the disparity between big and small cultivators.

The President has referred to the finalising of the Fourth Plan by the Planning Commission. He has rightly observed that our Plans would only be indicative of the future without any attempt to shape the future to suit our needs and aspirations unless they embodied our national will and determination to progressively bridge the gap between the needs and the resources in sight. We are glad to know from him that the government is determined to make every effort to

mobilise our own resources of savings, enterprise and managerial ability. But I hope our Planners would have given the desired direction to our planning which, to quote from the Second Five Year Plan was :

> "to plan the alignment of productive resources and of class relationships as to combine development with reduction in economic and social inequality: the process of development has to be socialised. The process of reducing inequalities is two-fold one. It must raise incomes at the lowest levels and it must simultaneously reduce incomes at the top. The former is basically the more important aspect."

The Mahalanobis Committee Report about the distribution of incomes had thrown light on the undesirable state of affairs before 1960. The fact disclosed by the Monopolies Commission Report is a refutation of our socialistic pattern. An All India Consumer Expenditure Survey by the National Council of Applied Economic Research, New Delhi published recently has revealed that the bottom 20 per cent of households in the developmental areas, share about six per cent of aggregate income of these areas. At the same time, the top 20 per cent of the households in these areas claims as much as 54 per cent of the aggregate income. The percentage of aggregate income shared by the bottom 20 per cent and the top 20 per cent in the underdevelopmental areas are 7 and 46 respectively. The percentage, besides, indicating the concentration of incomes in the hands of a few people in both the areas help to illuminate the fact that the inequalities of income in the developmental areas is more pronounced as compared to the non-developmental areas.

The President has reminded us of the Government's consciousness of the problems of integrated economic development in the country requiring political stability. The economic activities can only go on when we have a stable Government. The mid-term elections are over and we hope, in all these four States, a stable Government will be formed. But the formation of Government is not enough unless these Governments move their States in at least economic sphere an inch forward. So far, our experience upto now goes that non-Congress Governments have failed in moving their states in the economic sphere even an inch forward.

The President has, rightly, expressed his concern about some disquieting reports of a certain party or groups who did not allow the people to exercise their franchise. I hope, the Government will take necessary action. Here, I demand, through you, Sir, that what has happened in western districts of U. P. requires a Commission to go into all these details and report.

There is one more disquieting feature, a report from my constituency, that during the elections, a party or a group which is not known distributed a pamphlet in which they asked people to boycott elections and provoked people for armed revolution. I think, the Government should take due notice of this and put these miscreants indulging in nefarious activities to book.

Lastly, I am glad that the President has, very rightly, reminded us of the year of Gandhiji's birth centenary.

I am grateful to the President for its mention in his Address. Gandhiji's Birth Centenary is being celebrated not only in our country but in the other countries as well. But I wonder whether Ganhiji would have liked the manner in which we are celebrating his Centenary. When alive, he liked his birthday to be known as 'Charkha Jayanti'. Charkha symbolises a particular type of economic constitution and he himself has graphically described it. He said as early as 1928 :

> "According to me, the economic constitution of India and, for that matter, of the world should be such that no one under it should suffer from want of food and clothing. In other words, everybody should be able to get sufficient work to enable him to make both the ends meet. And this ideal can be universally

[Dr. Mahadeva Prasad]

> realised only if the means of production of the elementary necessaries of life remain in the control of the masses."

It would not be an exaggeration to say that Gandhiji was a more radical revolutionary than anybody may claim for. He seeks to combine Lincoln's love of liberty with Marx's passion for equality. Hence, the befitting manner in which the Birth Centenary of Gandhiji is to be celebrated is to pursue an effective non-violent strategy for establishing in India a fraternity that will embrace both liberty and equality. Towards this end, I would like to suggest two programmes for the year. Firstly, the Fourth Five Year Plan should be an Antyodaya Plan aiming at the amelioration of the lot of the 20 per cent people at the bottom who have not been benefited by the Plans which have been based on the theory of percolation. Secondly, for initiating the economic revolution, his theory of Trusteeship be put into practice in a practical manner. I have to add a few words in explaining the theory of Trusteeship of Gandhiji. Trusteeship is not a call to the conscience of businessmen and capitalists. It can never control their power to act irresponsibly. 'Power which is open to abuse must be controlled by power and not by conscience' as Mr. Paul Hayne has observed. Anybody who may care to study Gandhiji seriously can find clear and powerful sanctions for its implementation. Mr. Proudhon, the French philosopher said : 'All property is theft'. Gandhiji on the other hand said : 'All property is trust'. Both of them meant, however, the same thing. When Gandhiji asked any group or class to behave like trustees, he implied that they were behaving like thieves. They were thus served a notice to surrender their properties and power and share them with those whom they have been exploiting or dominating. 'If the owning class does not accept trusteeship voluntarily,' said Gandhi, '...its conversion must come under the pressure of public opinion.'

16.47 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

This is exemplified when he did not hesitate to ask the Rajpramukhs to accede to, and integrate with, the Indian Union.

Gandhiji anticipated the mood of the people at the dawn of Independence and, therefore, approved of a formula of trusteeship which was published in *Harijan* on the 26th October, 1952 in which the legislative regulation of ownership and use of wealth was not excluded. I am unable to go into the details for want of time. Gandhiji sent this formula to the Indian capitalists through Shri G. D. Birla. Shri Birla had accepted the principle of trusteeship as far back as 1929. But when Gandhiji came to brasstacks, the formula was kept in cold storage. No further communication from Shri Birla followed and Shri Pyare Lal, Gandhiji's Secretary, bears testimony to it in his book, *Last phase*.

Gandhiji was assassinated before he could pursue the matter any further. It is now more than twenty years since Gandhiji served notice on Indian capitalists through Shri Birla to quit privileges. They have shown no signs of a change of heart. On the other hand, they are entrenching themselves into positions of vantage with the help of foreign capital for more ruthless exploitation of the people. May the people of India expect that the persons at the helm of affairs in the country and eager to celebrate the Birth Centenary and those who claim to follow Gandhiji should devise an effective measure so that these recalcitrant trustees are obliged to fulfil their obligation ? May I say that, without this measure, it is not possible to build up the India of Gandhiji's dreams and it is meaningless to claim to endeavour to wipe every tear from every eye as the President would have liked to be done.

श्री वि० प्र० मंडल (माधीपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को देखने के पश्चात् जो सबसे बड़ी कमी हमें दिखलाई दी, वह यह कि कहीं भी हरिजनों, आदिवासियों, जन-जातियों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये कोई खास

जिक्र नहीं है। भारत की आवादी की परसेन्टेज को यदि लिया जाय तो आप देखेंगे कि इन पिछड़ी जातियों की आवादी सब मिलाकर करीब-करीब 80 प्रतिशत होती है और यदि अल्पसंख्यक-धर्मावलम्बियों को उनके साथ जोड़ दिया जाय, जिनकी अवस्था भी बहुत खराब है, तो 90 प्रतिशत से अधिक आवादी के बालिग लोगों के उत्थान के लिये इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। हिन्दुस्तान में 21 वर्षों से स्वराज्य के होने के बावजूद भी जब संसद में इस प्रकार की चर्चा आती है कि हरिजन को जिन्दा जला दिया गया या कहीं पर किसी हरिजन बालक को किसी कांट्रैक्टर या ठेकेदार ने बलिदान दे दिया तो समझ में नहीं आता कि इस देश का भविष्य कब सुधरेगा।

पढ़ने-लिखने की स्थिति को लीजिये। इन वर्गों के लोगों को शुरू से ही इस देश में पढ़ने-लिखने की जो सुविधायें मिलनी चाहियें, वे नहीं दी गई हैं। मनु स्मृति में, जो इस देश का संविधान था, लिखा गया है—यदि शूद्र के कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण हो जाय तो शीशे को घोलकर उसके कानों में डाल देना चाहिये—आज 21 वर्ष के बाद भी हम देखते हैं कि हरिजनों को जिन्दा जलाया जाता है। जिस देश में 90 प्रतिशत आदमी इन्सान की जिन्दगी नहीं, हैवान की जिन्दगी व्यतीत करते हों, जानवरों का जीवन विताते हों, वह देश यदि ऐसा कहे कि वह दुनिया के किसी भी देश के साथ कम्पीटीशन में खड़ा हो सकता है—तो यह सरासर गलत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश जो इतना सभ्य और पुराना देश है, उसके हजारों वर्षों तक गुलाम रहने का एकमात्र कारण यह भी हुआ कि यहां पर बहुत बड़ी तादाद को पढ़ने-लिखने से, शासनाधिकारों से, बड़े-बड़े पदों से और अन्य बातों से वंचित रखा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान एक हजार वर्षों तक गुलाम रहा और लोगों में यह मनोवृत्ति पैदा हो गई कि "कोई हो नृप हमें का हानि, चेरी छोड़ न हुइहें रानी।" आज जब इस देश में हरिजनों को जिन्दा जलाया जाता है तो समझ में नहीं आता कि यह देश कब चेतेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की बात कहता हूं। अन्य राज्यों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। जिन जातियों की आवादी सारे देश में 80-85 और 90 प्रतिशत है, यदि सरकारी नौकरियों में उनके आंकड़े देखेंगे तो आपको मालूम होगा, बिहार में उन जातियों का एक भी कलैक्टर नहीं है, एक भी जिला जज नहीं है, सब-जज शायद एक-आध कहीं पर हों। जिन जातियों की आवादी सैकड़े में पांच है, मंत्री मंडल में देखिये, सैकड़े में 95 वे लोग ही हैं, आई० ए० एस० की लिस्ट देखिये—सैकड़े में 95 वे हैं, कलैक्टरों की लिस्ट देखिये—वही हैं। ऐसा मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में सैकड़े में 95 आदमियों को उठाने की तरफ़ किसी का ख्याल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में मेहनत करने वाले आदमी कौन हैं। यदि आप खेती-हर मजदूर या मिलों में काम करने वालों के आंकड़े लेंगे तो आपको मालूम होगा कि अधिकांश काम करने वाले इन्हीं जातियों के हैं लेकिन उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। जहां आज दुनिया में इकानामिक-एक्सप्लायटेशन (आर्थिक शोषण) होता है, हमारे यहां दो तरह से शोषण होता है, आर्थिक शोषण के साथ-साथ सामाजिक शोषण भी होता है। हमारे यहां गांवों में विवाह के या श्राद्ध के अवसरों पर जो भोज होता है, उसकी झूठी पत्तलें जब फेंकी जाती है तो उसको खाने के लिये एक तरफ़ इन्सान और दूसरी तरफ़ कुत्ते दौड़ते हैं। अगर इकानामिक-एक्सप्लायटेशन ही इसका कारण

[श्री वि० प्र० मंडल]

होता तो ऊंची जाति के लोग भी इन झूठी पत्तलों को खाने के लिये दौड़ते। शहरों में 14 वर्ष की युवा अवस्था की अछूत लड़की सारा जीवन मल-मूत्र अपने सिर पर उठाती है। अगर इकानामिक एक्सप्लायटेशन ही इस देश में रहता तो और जातियों के लोग मल-मूत्र क्यों नहीं ढोते। हमारे देश में स्वराज्य आने के बाद रिक्शा चालकों की काफ़ी वृद्धि हुई है, इन रिक्शा वालों की जाति यदि आप पूछें तो सैकड़े में 95 रिक्शा चालक आपको हरिजन, पिछड़ी जाति के लोग, आदिवासी या मुसलमान मिलेंगे और दुख की बात है कि 21 वर्ष के बाद भी प्रेसीडेन्ट के एड्रेस में इन लोगों के लिये कहीं भी ज़िक्र नहीं है। हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी तादाद अन्धकार में है, जानवरों का जीवन व्यतीत करती है, उसको ऊपर उठाने के लिये किसी को फिक्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का बहुत दुख है और हम समझते हैं कि हिन्दुस्तान वास्तविक रूप में सबल नहीं हो सकता, जब तक हिन्दुस्तान में जात-पात के नाम पर आदमी आदमी में भेद माना जाता है, नीच समझा जाता है, जब तक यह भेद दूर नहीं किया जाता, हिन्दुस्तान सबल नहीं होगा और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसकी तरफ़ कोई इशारा नहीं है।

मैं समझता हूं कि हमारे संविधान के बनाने वालों ने खासकर वीकर-सैक्शन को तरजीह देने की जो बात कही है, उनकी यही मंशा थी और शायद डा० बी० आर० अम्बेदकर साहब यदि संविधान बनाने वालों में न रहते तो इन जातियों की तरफ़ ध्यान ही न दिया जाता। उनकी मंशा यही थी कि हिन्दुस्तान में जात-पात के नाम पर इन्सान-इन्सान का जो शोषण कर रहा है, वह समाप्त हो, लेकिन 21 वर्षों के बाद भी किसी का ध्यान इसकी तरफ़ नहीं है। यह बड़े दुख की बात है और राष्ट्रपति के भाषण में इसकी सरासर कमी है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल में हुए चुनावों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस बार चुनावों से पहले मैं चुनाव-आयुक्त से मिला था और वे बिहार भी गये थे। उन्होंने कहा था कि वे फेयर इलैक्शन करायेंगे, लेकिन बिहार में इस बार चुनाव का जो दृश्य हमने देखा, भगवान बचावे, अगर ऐसा ही चुनाव का दृश्य आगे रहा, तो प्रजातन्त्र इस देश में खत्म हो चुका है, आगे क्या खत्म होगा। प्रिसाइडिंग आफिसर बैठे रहते थे, जिसका मन होता, वोट गिरवाते रहते थे, एक-एक आदमी से 100-100 बार वोट गिरवाया गया। अगर कोई जांच करे तो मैं बूथ का नाम भी देने को तैयार हूं।...

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): 100-100 बार डाले?

श्री वि० प्र० मंडल: 100 ही नहीं 150 बार डाले।

श्री रणधीर सिंह: निशान नहीं लगाये?

श्री वि० प्र० मंडल: निशान को देखता कौन है, मार खायेगा क्या? प्रिसाइडिंग आफिसर्ज ने निशान की कोई परवाह नहीं की, निशान दिया ही नहीं, कहीं-कहीं पर तो प्रिसाइडिंग आफिसर ने खुद एक-एक हज़ार बैलेट देकर वोट गिरवाया। मैं समझता हूं कि शायद एक दिन में इलैक्शन कराने की क्षमता अभी हमारी सरकार में नहीं हुई है, लेकिन आपके प्रिसाइडिंग आफिसर होते कौन हैं? स्कूलों के टीचर होते हैं, छोटे दर्जे के आफिसर्ज होते हैं, शायद वे इतने काबिल नहीं हैं या शायद उनको बचाने के लिये वहां गार्ड वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, इसलिये वे इतने काबिल नहीं हैं कि चुनाव को ठीक से करा सकें। मैं यह

बात दावे के साथ कहता हूं, बिहार के अखबारों में भी ये समाचार बराबर निकल रहे हैं ..।

एक माननीय सदस्य : यू० पी० में तो उससे भी ज्यादा हुआ है।

श्री वि० प्र० मंडल : अगर यू० पी० में भी हुआ है तो और भी खराब बात है। तो बिहार में ऐसे ही चुनाव हुए। मुंगेर, जहां की बात मैं कहता हूं वहां हमारे हाशिम साहब, एडवोकेट उम्मीदवार थे। जब हमारी सरकार वहां थी, जबकि मैं मुख्य मंत्री था, तब वे हैल्थ मिनिस्टर भी थे। वे जीतने वाले थे लेकिन वहां के अफसरों ने, मुंगेर के डी० एम० और एस० पी० ने वहां पर कम्युनल रायट का एक सिलसिला खड़ा कर दिया और हाशिम साहब से कहा कि हम तुमको अरेस्ट करते हैं। इस तरह से लोग डर गए और मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया गया। तो इस तरह की बातें होती हैं। वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार आई० सी० एस० और एक जो जनसंघ का उम्मीदवार था दोनों एक जाति के थे, दोनों का संबंध था। इसलिए उन्होंने अपना फर्ज समझा कि किसी तरह से उसको जितायें। इसीलिए वहां पर हिन्दू मुसलमान का टेंश पैदा कर दिया गया। आज भी मेरे पास मुंगेर से बराबर तार आते हैं कि मुसलमानो को अरेस्ट किया जा रहा है। प्रेसीडेंट रूल में यह सब हो रहा है। यह बड़े दुख की बात है। इसलिए मेरा कहना है कि यदि हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र को जीवित रखना है तो इन बातों को बन्द करना होगा। एक समय में जब मैं कांग्रेस में था तो उस समय कांग्रेस डेलीगेट्स के चुनाव होते थे। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बन कर जाता था वह वहां बैठ कर जिसको चाहता था जिता देता था। उस वक्त मैं समझता था कि यह बात तो कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित है। लेकिन अब मैंने देखा कि आम चुनावों में भी वही बात की जा रही है।···(**व्यवधान**)···आम चुनावों में जो नजरिया पेश किया गया वह तो कांग्रेस आर्गेनाइजेशनल एलेक्शन से भी बदतर था। जिस प्रकार बिहार में चुनाव हुआ है अगर इसी प्रकार से चुनाव होता रहा तो फिर कोई भी रेस्पेक्टबल आदमी जो कि गुंडों को अपने साथ नहीं रख सकता है चुनाव में खड़ा नहीं होगा। जिसके हाथ में अधिक गुंडे रहेंगे वही बूथ को कंट्रोल कर लेगा। यह तो आपका चुनाव का सिलसिला रहा।

अब मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं कि चुनाव को किस प्रकार से ठीक से संचालित किया जाय। आप इसके लिए एक कमेटी या कमीशन की स्थापना करें। यह आवश्यक नहीं है कि पाश्चात्य देशों का मुकाबिला करके एक दिन में ही हम अपने चुनावों को समाप्त करने का प्रयत्न करें चाहे उसके लिए हमारे पास मजबूत मशीनरी हो या न हो। इससे आज हमारे प्रजातंत्र को बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर इसी तरह से चुनाव किये गए तो हमारा प्रजातंत्र खतरे में पड़ जायगा और खून खराबी भी होगी। अभी सात खून ही बिहार में हुए हैं। लेकिन इसी प्रकार से चुनाव हुए तो 700 या 7000 खून भी हो सकते हैं।

मैं और बातें न कह कर एक बात अंत में कहना चाहता हूं। हम देखते हैं कि चीन बराबर न्यूक्लियर पावर में अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन पर बहुत जोरदार एक्सपेरिमेंट किया है। चीन एक ऐसा देश है जिस पर हम कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमने देख लिया है कि उस में इन्सानियत की कितनी कमी है। अब अगर चीन किसी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन का निर्माण करता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत को उससे बचाने के लिए, भारत की रक्षा के लिए आप क्या उपाय सोच रहे हैं ? मैं इस

[श्री वि० प्र० मंडल]

बात को नहीं कहता कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि चीन के न्यूक्लियर वेपन्स से हिन्दुस्तान की सुरक्षा के उपायों की जानकारी इस देश को होनी चाहिए।

17 hours.

अन्त में मैं फिर यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान दुनिया के और राष्ट्रों का तब तक मुकाबिला नहीं कर सकता है जब तक कि यहां पर जो सामाजिक शोषण हो रहा है, जाति पाति के नाम पर एक आदमी दूसरे आदमी पर जुल्म कर रहा है, उसको बन्द नहीं किया जाता। जब तक हम इसका उपाय नहीं करेंगे तब तक हिन्दुस्तान का उत्थान नहीं हो सकता है। बड़े दुख की बात है कि इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है। अगर इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता तो हिन्दुस्तान कभी भी एक सबल राष्ट्र नहीं बन पायेगा।

श्री भोलानाथ मास्टर (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के भाषण में शुरू में ही बहुत ही सुन्दर बातें कही गई हैं खास तौर से कृषि की उपज और उद्योग धन्धों के संबंध में। मेरा निवेदन यह है कि यह दोनों चीजें कैसे आगे बढ़ सकें इस पर भी थोड़ा विचार करना होगा। मेरे पास वर्ल्ड बैंक की कटिंग है।

> "A recent World Bank survey tells the story of India's appaling poverty. With a per capita income of Rs. 675 per year, India figures 92nd in a list of 115 countries."

115 देशों में हमारे देश का 92वां नम्बर है। यह इस देश की हालत है। यह वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं जिसकी मदद के लिए हम उसे अक्सर हिन्दुस्तान में बुलाते हैं और उनके दौरे आयोजित करते हैं, कलकत्ता दिल्ली इत्यादि की सैर कराते हैं। इसी प्रकार से आगे उन्होंने एशिया में इंडिया की पर कैपिटा इनकम के बारे में हिसाब दिखलाया है

> "India ranks 22nd in per capita gross national product among 28 Asian countries."

एशिया में भी हमारा 22वां नम्बर है। अब मैं आपके सामने स्टेट-वाइज़ इनकम का हिसाब रखना चाहता हूँ। सारी स्टेट्स में पंजाब पर कैपिटा इनकम में सबसे ऊपर है। जहां तक राजस्थान का सवाल है वह बिहार से दूसरे नम्बर पर है। आंकड़े देने का मेरा मतलब यही है कि अभी इस देश में बड़ी जबर्दस्त कमियां हैं। दिनों दिन बेकारी बढ़ती जा रही है। हमारे राजस्थान के अन्दर डेंसिटी आफ पापुलेशन 92 के करीब आती है। और दूसरी तरफ बंगाल और केरल में जहां वामपंथी सरकारें बनी हैं वहां 400, 350 के करीब है। मैं मानता हूँ कि यह झगड़ा, यह तूफान जो इस आर्थिक अवस्था में पैदा हुआ है उसका कारण यह बढ़ती हुई आबादी भी है। इस बढ़ती हुई आबादी की बीमारी ने हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ़ में डाला है। हमारे नौजवान फ्रस्ट्रेशन में आकर यह सोचते हैं कि कौन सी ऐसी सरकार लायी जाय जिसके द्वारा हमको कुछ निजात मिले। जहां तक बेकारी की समस्या का सवाल है मैं और जगहों के बारे में तो नहीं कहना चाहता लेकिन जहां तक राजस्थान की बात है यह आंकड़े छपे हैं कि पिछले दो वर्षों में वहां पर 5 लाख 13 हजार आदमी बेकार थे और अब 9 लाख 31 हजार आदमी बेकार हो गए हैं। यह आंकड़े अभी अखबारों में छपे हैं। मैं अभी यह बता रहा था कि राजस्थान सब से पीछे है और हिन्दुस्तान एशिया में भी बहुत पीछे है और वर्ल्ड में तो पीछे है ही। आज जिस तरह से बेकारी बढ़ती जा रही है उसमें सिवाय इसके कि किसी भी सरकार के खिलाफ विद्रोह पैदा हो, गुस्सा बढ़े उसके

अलावा और कोई चीज हो नहीं सकती है। इसलिए हमें विचार करना होगा कि जो नया बजट पेश किया जा रहा है उसमें किस प्रकार से इसका समाधान निकाला जाय। मुझे एक बात पर बड़ा अफसोस होता है कि हर बात के लिए कोई कमीशन बना दिया जाता है लेकिन वह कमीशन कभी भी अपनी सिफारिशों को पूरा नहीं करा सकता है।

शिव सेना के बारे में जिक्र आया और सरकार ने महाजन कमिशन बनाया। अब मेरा कहना है कि अगर सरकार ने वह कमिशन बनाया था तो फिर उसकी सिफारिशों को उसने माना क्यों नहीं ?

सरकार कमिशन बैठाये और फिर उसे माने नहीं तो यह कौन सी बुद्धिमानी की बात है ? इसी तरीके से एजुकेशन का एक कमिशन बना दिया और उसने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी जिसे कि आदमी पढ़ते-पढ़ते थक जाय। कमिशन ने अपनी उस रिपोर्ट में लिख दिया कि अध्यापकों को अच्छे और बढ़े हुए वेतन दिये जायेंगे लेकिन सरकार वह वेतन अपने अध्यापकों को नहीं दे पा रही है। इसका नतीजा यह है कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर युनिवर्सिटी शिक्षा तक के जो अध्यापक हैं वह हड़ताल पर उतारू हैं। इसी तरीके से वह कल अखबारों में खोसला कमिशन की रिपोर्ट छप गयी कि पुलिस को कम तनख्वाह मिलती है। उसका मतलब है कि हड़ताल के लिए इनवीटेशन आ गया है अर्थात् या तो अब सरकार पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ाये वरना पुलिस वाले भी अध्यापकों की तरह हड़ताल कर देंगे।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी कमिशन बनाया जाय उससे पहले उसके सामने फ़ाइनेंशियल ऐस्पेक्ट जरूर रखा जाय। इस तरह की एक रिपोर्ट आप जरूर अपने सामने रखवा लीजिये। आज सुबह रेडियो बोल रहा था कि नेशनल लेबर कमिशन के बारे में गजेन्द्रगडकर साहब ने कोई बयान दिया है कि तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। अब वह कमिशन क्या रिपोर्ट पेश करेगा, फिर उसको मनवाने के लिए कितने रुपये की जरूरत है, कितना करोड़ या कितने अरब रुपया हमें चाहिए उसके लिए हमने क्या सोचा है ? रिपोर्ट छाप देते हैं लेकिन रिपोर्ट को मनवाने के लिए कितना फ़ाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर आने वाला है उसके बारे में पहले नहीं सोचा जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी डिबेट के ऊपर मेरा यह निवेदन है कि इस दृष्टि से भी इन कमिशनों के बारे में विचार किया जाना चाहिए। अगर हम कमिशनों की बराबर मांग करते रहेंगे लेकिन जो आशाएं उन कमिशनों के बनने से पैदा होती हैं उन आशाओं के अनुरूप यदि यह सरकार नहीं चलेगी तो चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह अध्यापक वर्ग हो, चाहे वह इंजीनियर हो और चाहे वह लेबर का कोई दूसरा वर्ग हो वह सब के सब विद्रोह करेंगे और इससे देश में अराजकता बढ़ेगी। इसलिए मेरा यह नम्र निवेदन है कि आज के बाद जब भी कोई कमिशन नियुक्त किया जाय तो उसके पहले उसके फ़ाइनेंशियल ऐस्पेक्ट को जरूर नोट कर लिया जाय। यह पता चल जाना चाहिए कि आप की मर्यादा इतनी है और इतना रुपया इस चीज में खर्च होने वाला है।

राजस्थान में राणावत कमिशन बनाया गया। उसने बड़ी अच्छी सिफारिशें कीं और वह पे कमिशन बनाया लेकिन उसे अमल में लाने के लिए राजस्थान सरकार के पास चूंकि पैसा नहीं था इसलिए नतीजा यह है कि वहां पर हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं और सरकार घबड़ा रही है। उधर अकाल पड़ गया राजस्थान के अन्दर और वह राजस्थान सरकार हमसे भी कहती है कि आप पार्लियामेंट में बैठते हैं इसलिए सरकारी लोन की जो किश्त लोगों पर ड्यू हो रही है उसको आगे बढ़वाइये। कहने का मतलब यह है कि इस

[भोलानाथ मास्टर]

तरीक़े से हालत हमारी बिगड़ती चली जा रही है। अजीब हालत है, एक तरफ़ सरकार कमिशन बनाती है और दूसरी तरफ़ जब उसकी सिफारिशों पर अमल करने का समय आता है तो कहती है कि उसके पास इसके लिए पैसा नहीं है। इसलिए इन सब बातों पर हमको विचार करना पड़ेगा।

फ़ाइनैंस कमिशन बैठाया हुआ है। मेरे खयाल से उसके सामने भी मैमोरेंडम पेश किया गया है। अख़बार में छपे समाचारों के अनुसार वित्त आयोग ने केरल सरकार के वेतन बिलों में हुई असामान्य वृद्धि की कड़ी आलोचना की है। वित्त आयोग ने केरल सरकार के बारे में जो औबजरवेशन किया है और वह अख़बारों में छपा है वह शायद उपाध्यक्ष महोदय ने भी पढ़ा होगा। मेरे पास उसकी रैलेवेंट कटिंग है जिसमें से कि मैं हाउस में कुछ लाइनें पढ़कर सुनाना चाहूंगा :

"केरल सरकार के अनियमित कार्यों की वित्त आयोग द्वारा कड़ी आलोचना।"

वित्त आयोग को बताया गया कि केरल सरकार ने पिछले 2 या 3 वर्षों में 12855 नये पद निर्माण किये थे जिनमें से 2355 पद राजपत्रित थे और 10500 अराजपत्रित इनके लिये प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ा।

मतलब इसका यह है कि सरकार अपने खर्च बढ़ाती चली जाती है। कितने ही उसने गजैटेड आफिसर्स बना दिये हैं और कितने ही नौन गजैटेड आफिसर्स बना दिये हैं लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं होता है तो वह फ़ाइनैंस कमिशन से मांग करती है या उसके वास्ते वह केन्द्रीय सरकार से झगड़ा करती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया कि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अच्छे सम्बन्ध होने चाहिएं लेकिन महज़ इस तरह की इच्छा प्रकट करने से तो यह चीज़ नहीं हो जायगी। यह ठीक ही है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अच्छे सम्बन्ध होने चाहिएं लेकिन वह सम्बन्ध अच्छे और ठीक कहां से होंगे क्योंकि जो रिसोर्सेज़ हैं जो साधन हैं वह तो सब सर्विसेज़ में, नौन प्रोडक्टिव कामों में जैसे तनख्वाहें अधिक से अधिक बढ़ाने में और सर्विसेज़ के वास्ते पे कमिशंस आदि बैठाने पर लग जाता है। उधर इंजीनियर लोग बेकार हो रहे हैं और दूसरी तरफ़ हम लोगों ने छोटे कर्मचारियों को 55 साल में रिटायर करना शुरू कर दिया है लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं कि आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और जो जजेज़ लोग बैठे हुए हैं उनकी रिटायरी की उम्र हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। नतीजा उसका यह है कि उन बड़े अफसरान के ऊपर तो खर्चा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि उनकी रिटायरी की उम्र बढ़ाते चले जा रहे हैं और उधर नीचे के लोगों को तनख्वाह भी पूरी नहीं दे पा रहे हैं। अब सर्विसैज़ की रिटायरी की उम्र के बारे में मेरा निवेदन है कि एक युनिफार्म पालिसी आप रखिये। अगर छोटे कर्मचारियों के लिए आप रिटायरी की उम्र 55 साल रखते हैं तो फिर बड़े अफसरान की भी रिटायरी की उम्र आप 55 साल रखें। सबको एक ही मियाद पर रिटायर किया जाय। यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि गरीब और छोटे कर्मचारियों को तो आप 55 साल की उम्र में रिटायर कर दें लेकिन वह बड़े-बड़े अफसरान जिनको कि 1000-1000 और 2000-2000 रुपये या उससे अधिक मासिक तनख्वाहें मिलती हैं उनको आप 58 साल में जाकर रिटायर करना चाहते हैं। हालत तो यह है कि बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों को 58 साल के बाद भी एक्सटैंशन मिल जाया करता है। 58 के बाद भी एक, एक और दो, दो साल तक उनको एक्सटैंशन मिल जाता है और जजेज़ तो काफ़ी बाद तक सर्विस में चलाये जाते हैं।

दूसरी तरफ़ हम देखते हैं कि हमारे देश के जजेज़ ने एक और नया तरीक़ा अख़तियार करना शुरू कर दिया है। जजेज़ हमारे पौलीटीशिएन हो गये हैं। मैं आज इस बात को साफ़ कर देना चाहता हूं कि भले ही श्री सुब्बाराव कितने ही अच्छे आदमी क्यों न रहे हों लेकिन वह सुब्बाराव राजनीति और राजनीतिज्ञों के चक्कर में पड़कर अपना सबसे बड़ा पद अर्थात् चीफ़ जस्टिस का पद तक छोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों की उम्र रिटायरी की बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मेरा कहना है कि यह जो दो स्टैन्डर्ड हम रखते हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और रिटायरी की उम्र हमें तमाम सर्विसेज़ के लिए एक ही रखनी पड़ेगी यह नहीं कि छोटों के लिए तो हम 55 कर दें और बड़े-बड़े अफ़सरान के लिए 58 कर दें।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि वह जो जिओलाजिकल सर्वे डिपार्टमैंट है उसके बारे में आप ज़रूर विचार करें। आपने खेती के बारे में विचार कर लिया, इंडस्ट्रीज़ के बारे में विचार कर लिया, लेकिन जो धन ज़मीन में पड़ा हुआ है उसके बारे में अभी तक नहीं सोचा गया है। ज़रूरत इस बात की है कि और नये-नये टैक्स लगाने के बजाय हम नये रिसोर्सेज़ की तलाश करें। राजस्थान में कौपर सबसे ज्यादा पाया जाता है। मेरे जिले में 40 जगहों पर कौपर की खानें हैं लेकिन अभी तक उसका सर्वे नहीं हुआ है। वहां पर बड़ा धन छिपा हुआ है और उसमें विदेशी सरकारें भी इंटरैस्टैड हैं। कभी-कभी पोलैंड की गवर्नमैंट बीच में आती है, कभी फ्रांस की गवर्नमैंट बीच में आती है या कांगो की गवर्नमैंट बीच में आ जाती है और उनमें यह कौपर के ऊपर झगड़ा हुआ। देश को वह कौपर के मामले में स्वावलम्बी नहीं होने देना चाहतीं तो इस तरीके के जो मिनरल्स हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा खोज की जानी चाहिए और इस तरह से अपने धन को बढ़ाने की तरफ़ ज्यादा ध्यान दिया जाय। ऐसा करने से हमारी समस्या हल हो सकती है। अभी हो यह रहा है कि नौन प्रोडक्टिव एक्सपैंडिचर रोज़ाना बढ़ता चला जा रहा है। रोज-बरोज कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। रोज गजैटेड आफिसरों और नौन गजेटेड कर्मचारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है लेकिन दूसरी तरफ़ जो रिसोर्सेज़ हैं जो डेवलपमैंट के सोर्सेज़ हैं चाहे वह सड़कें हों, चाहे खानों का विकास हो, उनकी तरफ़ कोई ध्यान नहीं है।

रिपोर्ट प्रकाशित होती है कि टैक्सेशन को सरल बनाया जाय। अब आज के अख़बारों में आपने पढ़ा होगा कि टायर्स बाज़ारों से ग़ायब हो गये हैं। अच्छी ब्रांड की सिग्रेटें भी गायब हैं। टायर्स और सिग्रेटों पर नया टैक्स लगाने की बात बाज़ार में उठ रही है। टैक्स के सवाल को लेकर शहर में एक हल्ला उठ गया। टैक्सेशन के बारे में श्री भूतलिंगम की रिपोर्ट आ गयी है। एक भूत की तरह उसकी रिपोर्ट लोगों के सामने आ खड़ी हुई है जोकि देश के अन्दर बेचैनी और बेक़रारी पैदा करे और सरकार के प्रति नफरत पैदा करे इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ वह करती नजर नहीं आती है। मेरा निवेदन यही है कि सरकार दूसरे सोर्सेज़ आफ़ रैवेन्यु तलाश करे और यह जो नौन प्रोडक्टिव एक्सपैंडिचर है उसको ख़त्म करे। सरकारी कर्मचारियों की रिटायरी की आयु की एक युनिफार्म सीमा तय करे। ऐसा न हो कि छोटे कर्मचारी तो 55 पर रिटायर कर दिये जायं और बड़े-बड़े अफ़सरान को आप 58 तक बनाये रक्खें। सोर्सेज़ आफ़ रैवेन्यु तलाश किये जायं, मिनरल्स की तलाश की जाय, नई खोजें कराई जायं और इस देश की वैल्थ को बढ़ाया जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Professor Ranga wants to add one more amendment to the Motion on Address by the President. I am permitting him to do so waiving the notice.

SHRI RANGA (Srikakulam): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

> "but regret that while referring to the industrial development of the country, the Address is silent regarding the steps proposed to be taken for the removal of regional imbalances specially in regard to the development of the backward areas. (558)"

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the President in his Address has referred to disturbing trends in parts of the country which have caused tension and violence, It must be admitted that there are symptoms and signs of disintegration of the nation and of the country in future. Many private organisations and forces are at work, as is evidenced from the Shiv Sena and the atrocities which they committed in Bombay. A stream of scorn, hatred and destruction was poured on the people of Bombay, specially on the minorites. There was large-scale arson, looting and burning. More than 50 lives were lost and the worst affected by them were those who came from South India, particulary the people of Mysore.

All these ugly incidents we must attribute to the series of mistakes committed by the Government of India, particularly by the Home Minister. It is not one mistake. There were a bundle or series of mistake for which the Home Minister must own his responsibility. It was a mistake to have reopened an already settled issue, an accomplished fact. It was a mistake to entrust it to the commission, in spite of the protests of the Government of Mysore. The Government of Mysore never wanted this issue to be re-opened. But their protests were ignored and a commission was appointed. When the commission was appointed a solemn assurance and an undertaking was given by both the Chief Ministers of Maharashtra and Mysore. But when the report of the commission came out, the Government and the people of Maharashtra backed out.

It was a mistake that the Government of India should have shoved back this report. For nearly two years it had not come to light. I do not know what were the reasons that led the Home Minister to put this report into cold storage. It was a mistake that the Government did not take speedy and immediate decision on this. Would any government wait for two years ? It was a Himalayan blunder. It was this that has created all difficulties. It was, again, a mistake on the part of Government to have nurtured and encouraged the Shiv Sena, a militant organisation, which has been the cause of all this.

I am speaking on behalf of all the people of Mysore and I ask that the Government of India must implement and honour the recommendations of the Mahajan Commission. No change or anything of that kind in it will be tolerated. After all, you must know that the people of Mysore have got their own self-respect, They form a part of India and they love the country. They are brave and they are not cowards. They are ready to meet any aggression but in the interest of the country they have held themselves back. So, I beg of the Government that by taking some other course and by adopting other measures they should not make this issue a more complicated one.

It was pointed out by an hon. Member here that Shri Nijalingappa has suggested that a judicial probe is necessary. I agree that it is absolutely necessary that there should be a judicial probe. There must be a probe as to how far we can allow these private militant organisations to function. They are proving a menace. I am sure, in course of time they will bring about disintegration and disruption of the nation.

Secondly, it is quite necessary to prevent attacks on the minorities to protect them.

What are the means that the Government will adopt for this ? In fact, there were signs, not only now but six months back. There were attacks on the minorities by the Shiv Sena and no action was taken.

Shri Kripalani just now stated that emotional integration is not achieved by emotion alone ; it must be by the rule of law. Was there rule of law in Bombay ? I will not be wrong in saying that the Government of Maharashtra is sympathetic towards this. I must state that this was started when Shri Chavan was the Chief Minister of Maharashtra. He is the originator and the man who has kept alive this organisation.

Again, it must be remembered that Bombay is a cosmopolitan city. There must be peace and harmony amongst all. There are a number of minorities. There are Muslims, Parsis, South Indians and Mysorians. What are the steps that the Government is going to take to protect them and to safeguard their interests ? If these things continue, the Government should think seriously to make Bombay a Union territory to be administered by the Centre. It is a cosmopolitan city Everybody has a right to live there. If the Shiv Sena, by its forces, want to harass and destroy the minorities it will be a very serious matter.

About Belgaum city, there were two judicial opinions, two competent tribunals, by persons of eminence who went into all this and awarded it to Mysore. One was the S. R. C. which said that it must go to Mysore. Again, the Mahajan Commission has said that it should go to Mysore. Are these two judicial opinions important or the agitation of Shiv Sena ? All will agree that when the recommendations come from an authority like this, from persons who are eminently placed and who are unconnected with Mysore, they must be honoured. The Government of Maharashtra is behaving like a common litigant. When an ordinary litigant finds that the case has gone against him, when the judgment is adverse to his interests, he simply begins to blame the judge. The same thing is happening here. In fact, there have been a series of findings by competent tribunals that Belgaum belongs to Mysore. Still they are not satisfied. They go on protesting against it. Is this fair ?

I must say one thing that the people who have suffered are mostly Mysoreans. They must be given compensation. It has been suggested by the Congress President himself. Their interests must be protected

AN HON. MEMBER : The Chief Minister of Mysore has also said it.

SHRI J. MOHAMED IMAM : Yes. They must be given compensation. The first thing is that the Government must consider how to ensure the safety and the well-being of the minorities, whether they come from south or from north, and how to ensure and see that they have a comfortable living. On the other hand, if the Government keeps quiet, if the Shiv Sena goes on spreading these activities and becomes more and more powerful, and there is no place for minorities to live there, it will become a very serious matter. The Government must consider that.

Again, I must refer to the dispute between Mysore and Maharashtra over Krishna-Godavari waters which is creating more tension between them. The Mysore Government, for the last 10 years, have been asking the Government of India to appoint a tribunal to settle the dispute. Two years have elapsed and yet they have not taken any step in the matter. Now, Dr. K. L. Rao wants to make it more complicated by saying that he wants to appoint two tribunals which will not be acceptable to Mysore. What the Mysore Government says is that all the complications are created by Dr. K. L. Rao just to gain time and to see that the second phase of Nagarjunasagar is completed.

Again, the Mysore Government has been complaining that it has been receiving step-motherly treatment and that there has been delay on the part of the Central Government in giving clearance to various industrial concerned. In fact, there is a move to transfer the expansion of the Bharat Electronics and the Indian Telephone Industries to some other places whereas it will be more economical and more advantageous to expand the existing

[J. Mohamed Imam]

factories where they are. That is how the public sector projects are failing. That is how they are working at a loss. They have no idea that it is advantageous to expand existing factories rather than to move to some other places.

Lastly, I say, I am only speaking in the interest of the country that the nation must be united. I think, the Home Minister must take a strong hand on the activities of the Shiv Sena. In fact, I am sorry that he has been kept in an embarrassing position by entrusting him to decide the issue. He has kept it for two years. If the same subject had been handled by some other Minister, he would at least have brought the Mahajan Commission Report before Parliament and implemented it.

17.30 hours.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

EXPORT OF MANGANESE ORE TO NORTH KOREA

MR. DEPUTY-SPEAKER : Before we start the half-an-hour discussion, I would like to remind the hon. members that we would follow the procedure that has been laid down. That is, the hon. member who raises the discussion will get his time, about 10 to 12 minutes, and then the hon. Minister will reply. Then the other hon. members, whose names have come in the ballot, will be permitted to put questions for further clarification.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : माननीय सदस्य इनिशिएट तो करें लेकिन उनके बाद जिनके नाम हैं, उनको सवाल पूछने की इजाजत दीजिये । जवाब के बाद अगर आपने दूसरों को सवाल पूछने का अवसर दिया तब रैपीटीशन हो जायगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is the procedure that is laid down. If the hon. Member wants any change, he may take up the matter in the Rules Committee.

Mr. Patodia.

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, sometime back, one more country has arisen in the trade horizen of India, a country with whom trade relations had been suspended at the time of Chinese attack because that country was a close ally of China. According to the facts and figures that we have got, that country, North Korea, has started trading with India, and in 1967-68 India exported as much as 10,000 tonnes of manganese ore to that country.

There could be no objection to any normal trading activities with any country. But trading with North Korea causes suspicion, causes doubt, on account of several factors involved. The first consideration is what induced India, what were the factors that impelled India, to trade with a country with whom India suspended trading activities at the time of Chinese attack, a country which is known for its alliance and sympathies with our enemy.

Secondly, the very pattern of trade with North Korea, the very pattern of agreement, gives us a suspicious feeling as to what is boiling within the pot.

17.32 hours

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the chair*]

Even in reply to Unstarred Question No. 1 on which this discussion has been raised, the hon. Minister was conspicuously confusing. Before I raise my points, please permit me to quote from the reply given by the hon. Minister. The question was :

"(a) Whether it has been decided to allow the export of manganese to North Korea; and

(b) if so, the quantity of manganese ore likely to be exported, the price charged for the same; and

(c) how this price compares with the prices in the world market."

The answer was amall and simple. It says :

"(a) Yes, Sir.

(b) & (c) : Contracts have yet to be concluded."